राष्ट्रीय हिन्दी साप्ताहिक अखबार

वर्ष : 05 अंक 05
पृष्ठ : 8
मूल्य : 2.00/– रु.
UPHIN/2014/67765

क्राइम रिव्यू

साहस सच लिखने का

लखनऊ,
शनिवार , 07 जुलाई 2018
www.crimereview.co.in
www.facebook.com/crimereview
@crimereview2012

अब सूखाग्रस्त इलाकों में कृत्रिम बारिश कराएगी योगी सरकार

लखनऊ। सूखे से निपटने के लिए सूबे की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत सरकार कृत्रिम बारिश कर कराकर किसानों को राहत देगी। इस कृत्रिम बारिश के लिए हेलीकाप्टर का इस्तेमाल किया जायेगा। इस योजना को पूरा करने में आइआइटी कानपुर सीएम योगी आदित्यनाथ की मदद करेगी। प्रोजक्ट भी तैयार कर लिया गया है।

अब इस प्रोजेक्ट को अमलीजामा पहनने के लिए सिंचाई विभाग काम कर रहा है। हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह के हवाले से कहा गया है कि सूखे से किसानों को निजात देने और कृषि की पैदावार बढाने के लिए योगी सरकार ने ये बड़ा

फैसला लिया है। हेलीकाप्टर द्वारा एक हजार किलोमीटर में इस कृत्रिम बारिश के लिए 5.5 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

मंत्री धर्मपाल ने बताया कि पर्याप्त बारिश न होने की स्थिति में मानसून खत्म होने के बाद बुंदेलखंड से कृत्रिम बारिश प्रोजेक्ट की शुरुआत होगी। राज्य के सभी सूखा प्रभावित जिलों में इस सुविधा का लाभ किसान उठाएंगे। इस योजना के तहत पहले तो प्राकृतिक गैसों से कृत्रिम बादल तैयार किये जायेंगे। उसके बाद जिन इलाकों में बारिश कराने की जरुरत पड़ेगी वहां आसमान में हेलीकॉप्टर से सिल्वर आयोडाइड और कुछ दूसरी गैसों का घोल उच्च दाब छिड़का जाएगा।

इस केमिकल के छिडकाव से वहां बारिश होगी। में सिंचाई विभाग इस तकीनीकी को जानने के लिए आइआइटी कानपुर के विशेषज्ञों से जानकारी हासिल कर चुका है।खास बात है कि ऐसी बनावटी बारिश के लिए आइआइटी कानपुर ने तमाम उपकरणों का बंदोबस्त भी कर लिया है। आपको बता दें कि दुनिया में कई देश इस कृत्रिम बारिश (शेष पृ. 7 पर). . .

15 जुलाई से पॉलिथिन और प्लास्टिक पर यूपी में पूरी तरह बैन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरी बार प्रदेश में आगामी 15 जुलाई से पॉलिथिन और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। बाराबंकी में वृक्षरोपण कार्यक्रम समारोह के दौरान शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में 15 जुलाई से पॉलिथिन और प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया जायेगा। उन्होंने कहा 15 जुलाई के बाद प्रदेश में प्लास्टिक और पॉलिथिन का उपयोग न, हो इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना है। श्री योगी ने पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे सहयोग की अपील की करते हुए कहा कि 15 जुलाई के बाद पर्यावरण को नुकसान पहुंचने वाले प्लास्टिक से बनी सामग्री एवं सामान के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए

मिलकर काम करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रदेश में नौ करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। श्री योगी ने शुक्रवार को बाराबंकी के रामनगर क्षेत्र में लोधेश्वर महादेव मंदिर में आयोजित वन महोत्सव में कहा कि इन पौधो के लगने से जमीन में नमी बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते 15 जुलाई से पूरे प्रदेश में पॉलीथिन (प्लास्टिक) को बंद कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कहा कि इस साल वन महोत्सव का कार्यक्रम करने के लिए इस जगह को इसलिए चुना गया है कि विधानसभा चुनाव के दौरान मुझे यह शिकायत मिली थी कि महादेवा के साथ भेदभाव होता है। मुझे लोगों ने बताया था कि इस स्थान पर बिजली नहीं आती है पिछली सरकार में इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया था।

आजम खान के खिलाफ एक और जांच शुरु

मौलाना जौहर अली शोध संस्थान और जौहर अली ट्रस्ट को सस्ती दरों पर जमीन देने के मामले में शुरू

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और अखिलेश सरकार में मंत्री रहे आजम खान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उत्तर प्रदेश एसआईटी ने आजम खान के खिलाफ एक और जांच शुरू कर दी है। एसआईटी ने यह जांच मौलाना जौहर अली शोध संस्थान और जौहर अली ट्रस्ट को सस्ती दरों पर जमीन देने के मामले में शुरू की है।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी ने आजम खान के खिलाफ जांच को आगे बढ़ाते हुए इस मामले में रामपुर जिलाधिकारी से दस्तावेज तलब किए हैं। बता दें कि इसके पहले जल निगम भर्ती घोटाले में आजम खान के खिलाफ यूपी पुलिस की एसआईटी ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

एसआईटी पूर्व की अखिलेश सरकार में जल निगम में हुई 1342 लोगों की भर्ती में हुई अनियमितताओं की जांच कर रही है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि भर्ती के दौरान नियमों को दरकिनार करते हुए गलत नियुक्तियां की गई।

वहीं, भाजपा की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि सपा के कार्यकाल में हुई हर सरकारी विभाग की भर्तियों की जांच कराएंगे। एसआईटी ने अब मौलाना जौहर अली शोध संस्थान और जौहर अली ट्रस्ट को सस्ती दरों पर जमीन देने के मामले में आजम खान के खिलाफ जांच शुरू की है।

14 माह पहले यूपी में कृषि मंत्री ने कृषि भवन नहीं देखा था : केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह

लखनऊ में आज कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं. वहीं उनके साथ प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और रणवेंद्र सिंह भी कृषक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए.

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कृषक सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह शामिल हुए हैं. इस दौरान उन्होंने उपस्थिति लोगों को सम्बोधित करते हुए न केवल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही विपक्षियों पर भी हमला बोला.

केन्द्रीय कृषि मंत्री ने सम्बोधन में कहा कि विरोधियों के पास कुछ मुद्दा नहीं इसलिए कुछ न कुछ तो बोलेंगे. दलहन तिलहन पिछले 4 बरस से पहले देश मे मात्र 8 लाख टन खरीद होती थीहमारी सरकार ने 64 लाख

टन दलहन खरीद की. यूपी का दुर्भाग्य था कि 14 माह पहले इस राज्य के कृषि मंत्री ने कृषि भवन नहीं देखा था. किसान धीरे धीरे मानने लगा है कि उसकी आमदनी दोगुनी हो सकती है. जिन्हें काली गाय और भैंस में पहचान नहीं वो इसपर विश्वास नहीं कर रहे. यूपी की धरती ने देश को पीएम और गृह मंत्री दिया. आजादी के बाद किसानों के लिए इतना बड़ा फैसला अभी तक नहीं हुआ था. बुवाई से लेकर कटाई तक लागत से डेढ़ गुना किसानों को मूल्य का फैसला लिया. विरोधी भी अकेले में मिलकर कह रहे हैं कि बड़ा ऐतिहासिक फैसला है. विरोधियों के पास कुछ मुद्दा नहीं इसलिए कुछ न कुछ तो बोलेंगे. MSP में इतनी बढ़ोत्तरी आजादी के बाद से कभी नहीं हुई. पीएम मोदी ने कहा, खजाने पर किसानों का पहला अधिकार है. दलहन तिलहन पिछले 4 बरस से पहले देश मे मात्र 8 लाख टन खरीद होती थी. हमारी सरकार ने 64 लाख टन दलहन खरीद की.

मादक पदार्थों के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के निर्देश

लखनऊ डीजीपी ने दिए अधिकारीयों को मादक पदार्थो के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने के निर्देश पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने मुख्यालय के सभागार में मादक पदार्थो के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु बैठक सभी अधिकारीयों की बैठक बुलाई। इस बैठक में पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध संगठन, अपर पुलिस महानिदेशक, आर्थिक अपराध संगठन, अपर पुलिस महानिदेशक, लखनऊ जोन, अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, पुलिस महानिरीक्षक एटीएस, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ लखनऊ एवं पुलिस अधीक्षक, अपराध मुख्यालय सम्मिलित हुए। बैठक में डीजीपी ओपी सिंह ने मादक पदार्थो के अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने हेतु निम्न निर्देश दिये 1– मादक पदार्थो के (शेष पृ. 7 पर). . .

राजभर की भाजपा को ललकार, कहा– हिम्मत है तो कैबिनेट से बाहर करके दिखाएं

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई वाली भारतीय समाज पार्टी (एसबीएसपी) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बीच विवाद बढ़ गया है। कैबिनेट मंत्री ने भाजपा के खिलाफ बयानबाजी कर मोर्चा खोल दिया है, उन्होंने कहा कि बीजेपी हमें गठबंधन से निकालने की धमकी देती है। हिम्मत है तो हमें कैबिनेट से निकाल कर दिखाएं। एसबीएससी ने भाजपा अध्यक्ष डॉ महेंद्र नाथ पांडे के खिलाफ चांदौली लोकसभा सीट से वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में सुनील पटेल को मैदान में उतारने की घोषणा की है। श्री पांण्डेय चंदौली सीट से मौजूदा भाजपा सांसद है। हाल ही में एसबीएसपी और भाजपा अध्यक्ष के बीच का विवाद

सार्वजनिक हो गया था। बुधवार की शाम को राज्य की राजधानी लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक के दौरान ओमप्रकाश राजभर ने घोषणा की है कि अब भाजपा के साथ सीधी लड़ाई होगी। वे अति पिछड़ों को आरक्षण दिये जाने के मुद्दे पर पीछे नही हटेंगे। एसबीएसपी ने पिछड़ों के लिए 27 प्रतिशत कोटे में से अति पिछड़ों को भी आरक्षण देने की मांग की है। श्री राजभर ने गुरूवार को यहां कहा कि उनकी पार्टी को इस बात की कोई चिन्ता नही है कि भाजपा उन्हें कैबिनेट से बाहर कर दे। उन्होंने कहा, ष्पार्टी राज्य की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। यदि भाजपा हमारी मांग पर विचार नही करेगी तो एसबीएसपी निर्णय लेने के लिये (शेष पृ. 7 पर). . .

यूपी की जनता 74 सीट देकर दोबारा मोदी को बनाएगी पीएम : शाह

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने अखिलेश यादव और मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अगर बुआ–भतीजे हाथ मिलाते हैं तो लोकसभा चुनाव में थोड़ा फर्क पड़ेगा। इस अंतर को मिटाने के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं को मत प्रतिशत 44 से ऊपर 51 प्रतिशत तक ले जाना होगा। लोकसभा में बहुमत का रास्ता यूपी से निकलेगा। उत्तर प्रदेश की जनता से भाजपा को उम्मीद थी वर्ष 2014 में 65 सीट देगी लेकिन नरेंद्र मोदी पर अपना प्यार लुटाते हुए 71 सीट दे दी थी। शाह ने विश्वास जताया कि मिशन 2019 में यूपी की जनता मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए इस बार 74 सीट देगी।

पंडित दीनदयाल हस्तकला संकुल, बड़ालालपुर में भाजपा के सोशल मीडिया वालंटियर्स मीट में कार्यकर्ताओं से संवाद करने पहुंचे भाजपा अध्यक्ष ने मिशन 2019 का साइबर शांखनाद किया। कहा कि 15 अगस्त के बाद पूरा देश चुनावी मोड में आ जाएगा। सोशल मीडिया के माध्यम से हम जनता के बीच जाकर मोदी और योगी सरकार की योजनाओं को बताएंगे (शेष पृ. 7 पर). . .

उप्र एससी/एसटी आयोग ने आरक्षण मसले पर एएमयू को भेजा नोटिस

लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (एससी ध्एसटी) आयोग ने दलित आरक्षण मुद्दे पर बुधवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (एएमयू) प्रशासन को नोटिस भेजा है। राज्य एससी ध्एसटी आयोग अध्यक्ष बृजलाल ने पत्रकारो को बताया कि एएमयू आरक्षण के संबंध में अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाहन करने असफल रहा है। उन्होने बताया कि आयोग ने कुलसचित एएमयू को नोटिस भेजा है और आठ अगस्त तक जवाब मांगा है। उन्होने कहा कि आयोग ने पूछा है कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है तो फिर किन वजहों से विश्वविद्यालय में आरक्षण व्यवस्था लागू नहीं की गयी है।

इससे पहले अलीगढ़ में एएसी/एसटी आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष राम शंकर कठेरिया ने मंगलवार को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उप कुलपति तबस्सुम शहाब के साथ सर्किट हाउस में दलितों और पिछिडों के आरक्षण को लेकर बैठक की। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष ने पूछा कि एएमयू में दलितों व पिछड़ों का दाखिला किस आधार पर नहीं किया जा रहा है। आयोग ने पूछा कि 2005 में एएमयू के आरक्षण का मामला उच्चतम न्यायालय में आया तो उससे पहले आरक्षण को लागू क्यों नहीं किया गया।

अब बीएड डिग्रीधारक भी बन सकेंगे प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में पिछले कई सालों से सरकार और क्षिक्षकों या क्षिक्षक बनने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों में रस्साकशी चल रही थी. लेकिन इस बार जो खबर सामने आई है, उससे बीएड अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ गई है. दरअसल, अब बीएड उत्तीर्ण छात्र भी प्राइमरी स्कूल के शिक्षक बन सकेंगे. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) ने प्राथमिक स्कूलों में अध्यापक बनना और आसान कर दिया है। परिषद ने प्राइमरी स्कूलों में अध्यापक बनने की योग्यता में संशोधन करते हुए बीएड को भी शामिल कर लिया है। इसके लिए छात्रों के स्नातक में 50 फीसदी अंक होने चाहिए. नियुक्ति के बाद ऐसे शिक्षकों

को दो वर्ष के अन्दर छह महीने का ब्रिज कोर्स भी पास करना होगा.

इस खबर के साथ ही बीएड डिग्रीधारकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। उत्तर प्रदेश में बीएड की दो लाख सीटे हैं। एनसीटीई द्वारा प्राइमरी स्कूलों में भर्ती के लिए दो साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रम की योग्यता देने से बीएड डिग्री धारको में मायूसी थी। हालांकि इस खबर के बाद एक बार फिर बीएड डिग्री धारकों में खुशी का माहौल है.

एनसीटीई ने भले ही बीएड डिग्री धारको को प्राइमरी स्कूलों में शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर दिया है. लेकिन इसके लिए उसने कुछ मानक (शेष पृ. 7 पर). . .

छात्रों के भारी विरोध पर लखनऊ विश्वविद्यालय बंद, काउंसलिग रोकी

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय में 2 जुलाई से छात्र भूख हडताल पर है. जिसके बाद विश्वविद्यालय परिसर में माहौल और गर्म हो गया. छात्रों के एडमिशन को लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और शिक्षकों के बीच हाथपाई तक हो गयी. कई छात्र घायल भी हुए , वहीं इस सब के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय को बंद भी कर दिया गया. नाराज शिक्षकों में काउंसलिंग भी रोक दी हैं.

लखनऊ विश्वविद्यालय (एलयू) के गेट–1 पर 2 जुलाई से अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं. इस दौरान पूजा शुक्ला सहित कई छात्र भूख हडताल पर बैठे थे. दरअसल, एलयू की ओर से पीजी प्रवेश परीक्षा में आवेदन करने वाले तीस अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक

दिया गया है।

इस कारण अभ्यर्थियों ने कैंपस में धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। छात्रों का कहना है कि जब तक विवि प्रशासन रिजल्ट नहीं जारी करता तब तक धरना जारी रहेगा।

एडमिशन की मांग को लेकर धरना कर रहे छात्रों ने प्रदर्शन करने से पहले सुबह ग्यारह बजे अभ्यर्थी एलयू के प्रॉक्टर विनोद सिंह के पास पहुंचे और रिजल्ट रोकने का कारण पूछा।

कहा कि हमारे ऊपर ऐसे कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं जिससे विवि का माहौल हम खराब कर देंगे। अभ्यर्थियों ने कारण लिखित में देने को कहा तो प्रॉक्टर ने इसपर साफ इनकार कर दिया।

अभ्यर्थियों के मुताबिक, प्रॉक्टर ने कहा कि उनपर ऊपर से प्रेशर है इसलिए वह कुछ भी लिखकर नहीं दे सकते, इसपर अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। भूख हड़ताल पर बैठीं पूजा शुक्ला ने बताया कि मंगलवार को एमएलसी सुनील सिंह साजन व अन्य नेता भी समर्थन करने के लिए आ रहे हैं।

समाजवादी छात्र सभा के पदाधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि विवि को अगर बाहर ही करना था तो वह आवेदन के समय कर देते। अब उचित कारण तो बताएं कि हमे किसलिए ऐडमिशन नहीं दिया जा रहा।

सिर्फ वीसी का मन नहीं है इसलिए (शेष पृ. 7 पर). .

ओरिएंटेशन प्रोग्राम के साथ लोहिया विवि का नया सत्र शुरू

लखनऊ। डा. राम मनोहर लोहिया विधि विविद्यालय में नया शैक्षिक सत्र बृहस्पतिवार से शुरू हो गया। नये सत्र की शुरुआत पहले दिन ओरिएंटेशन प्रोग्राम से हुई। जिसमें नवआगन्तुक छात्र–छात्राओं को कुलपति प्रो. एसके भटनागर ने सम्बोधित किया। उन्होंने छात्रों से रैगिंग से दूर रहते हुए अनुशासन बनाए रखने और पढ़ाई पर ही ध्यान देने का आह्वान किया। चीफ प्राक्टर डा. एके तिवारी ने छात्रों से कहा कि वह उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए हर समय उपलब्ध रहेंगे। विविद्यालय की प्रवक्ता डा. अलका सिंह ने बताया कि बृहस्पतिवार छह जुलाई से कक्षाएं शुरू हो जाएंगी।गठित किया नया प्राक्टोरियल बोर्ड रू विधि विश्विद्यालय के नये कुलपति प्रो. एसके भटनागर ने नया प्राक्टोरियल बोर्ड भी गठित किया है। बोर्ड में चीफ प्राक्टर का नया पद सृजित किया गया है। चीफ प्राक्टर डा. एके तिवारी और प्राक्टर डा. पीके गौतम को बनाया गया है।

जल्द होगा योगी कैबिनेट में बड़ा बदलाव, इन मंत्रियों की होगी छुट्टी तो इन्हें मिलेगी जगह

लखनऊ। आगामी लोकसभा चुनावों को मद्देनजर सूबे की योगी सरकार मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव करने जा रही है। इस बदलाव ये बदलाव जुलाई की आखिरी सप्ताह या अगस्त के पहले हफ्ते में हो सकता है। खबरों की माने तो मंत्रिमंडल में बदलाव के साथ तहत एक बड़ा बदलाव किया जाना है। जहाँ नए चेहरों को जगह मिलेगी वहीँ कई लोगों की छुट्टी भी होने की संभावना है। केंद्र सरकार के विभागों की तरह उत्तर प्रदेश के बिखरे विभागों समन्वित नहीं कर पाया उन्हें समेटने की सलाह दी गयी है।

के अंतर्गत सरकार की उपेक्षा पर खरे न उतरने वाले कई मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है। साथ कई नए चेहरे भी मंत्रिमंडल का हिस्सा बन सकते हैं। कहा जा रहा है कि विभागों की संख्या भी कम की जा सकती है। सूत्रों की माने तो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी और संघ मंत्रीमंडल में बदलाव को लेकर चर्चा कर रही है। इसी के खबरों की माने तो अवध, कानपुर, गोरखपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय संगठन मंत्रियों के रिक्त पदों पर तैनाती की जा सकती है। इसके साथ ही निति आयोग

सांसदों व विधायकों पर केस के लिये अलग से कोर्ट बनी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग ने अब नई व्यवस्था बनाई है, जिसके तहत सांसदों व विधायकों पर केस के लिये अलग से कोर्ट बनाई जायेगी। उत्तर प्रदेश के न्याय विभाग ने हाईकोर्ट को आज पत्र भेजकर अवगत कराया है कि सांसदों और विधायकों पर केस के लिये अलग से कोर्ट स्थापित की जा रही है। इस कोर्ट में एचजेएस स्तर के एक जज नामित होंगे। न्याय विभाग के अनुसार कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूरा उत्तर प्रदेश होगा। इस नई व्यवस्था के अनुसार अब सांसदों व विधायकों पर केस के लिये सुविधा होगी।

ग्राम रऊ करना में ग्राम स्वराज अभियान के तहत लगी चौपाल

उन्नाव। ग्राम स्वराज अभियान के तहत चौपाल कार्यक्रम का आयोजन ग्राम रऊ करना में किया गया,बिंदु वार सरकारी योजनाओं के बारे में अधिकारियों ने ग्रामीणो को जानकारी दी और उनके निदान के लिए मुख्य बिकास अधिकारी श्री प्रेम रंजन सिंह ने आदेश दिया ग्राम सभा रऊ करना गांव में जिलाधिकारी का चौपाल कार्यक्रम आयोजित होना था उनके न आने पर मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में चौपाल लगाई गई जिसमें अपर पुलिस अधीक्षक एस.पी. सिंह,मुख्य चिकित्साधिकारी लालता प्रसाद एवं विभिन्न विभागों के अधिकारीगण सहित फरियादी मौजूद थे। प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 73 नये खाता खोले गए जीवन ज्योति योजना, सुरक्षा बीमा योजना, मिशन इंद्र धनुष योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व योजना के बिषय में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ लालता प्रसाद ने विस्तार से गामीणो को जानकारी दी उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आयुष मान भारत योजना शुरू होने वाली है इस योजना के तहत पांच लाख रुपए तक का सालाना इलाज मुफ्त में होगा जुलाई माह को संचारी रोग माह मनाया जा रहा है इस माह में बीमारियाँ अधिक पनपती है जिससे बचने के लिए जागरूक रहने की आवश्यकता है।

पेंशन योजना में 115 पात्र लोगों को योजना में शामिल किया गया है निशुल्क बोरिंग योजना में छ पात्र किसानों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना में पूर्व में 16 आवास दिये गये थे 17ध्18 मे 05 आवास और 18ध्19 मे 04 और पात्र लोगों को इस योजना में शामिल किया गया है। जिला कृषि अधिकारी ने फसल बीमा योजना व किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में जानकारी दी। स्वच्छ भारत मिशन के विषय में डी पी आर ओ ने बताया कि 805 शौचालयों का लक्ष्य रखा गया था जिसमें 425 शौचालय बन कर तैयार हो गए हैं और शेष पर कार्य चल रहा है गाम प्रधान दारा 15 अगस्त तक खुले में शौच मुक्त करने का आश्वासन दिया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने आवास योजना के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 05 वर्षों में किसी का भी कच्चा मकान नहीं बचेगा सभी पात्र लोगों को इस योजना के तहत आवास दिये जायेंगे।

मंत्री आशुतोष टंडन ने किया मेट्रो रूट का निरीक्षण

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा व प्राविधिक शिक्षा मंत्री श्री आशुतोष टण्डन ने आज लखनऊ के ट्रांस गोमती क्षेत्र में मेट्रो के निर्माणाधीन रुट एवं स्टेशनों का निरीक्षण किया। इस क्रम में हनुमान सेतु के निकट गोमती पर पुल (यह 85 मीटर लम्बा बगैर खम्भे का पुल है), आईटी कालेज चौराहा, पुलिस लाइन मेट्रो स्टेशन, इंदिरा ब्रिज के निकट 60 मीटर लम्बा बगैर खम्भे का पुल, बादशाह नगर मेट्रो स्टेशन, कुकरैल नाले के ऊपर डबल हाइट ब्रिज, लेखराज स्टेशन, राम सागर मिश्रा स्टेशन, इंदिरा नगर स्टेशन तथा

अंतिम मेट्रो स्टेशन मुंशीपुलिया इन समस्त रुट का निरीक्षण किया।चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इसके साथ ही मेट्रो के मार्ग में ट्रांसगोमती क्षेत्र में पड़ने वाले चार नालों का भी निरीक्षण किया और संबंधित मेट्रो एवं नगर निगम के अधिकारियों को निर्देशित किया कि नालों की शीघ्र मरम्मत कराया जाए ताकि बारिश के कारण जलभराव न होने पाए।श्री टण्डन ने बताया कि पालीटेक्निक चौराहे पर पड़ने वाले 03 स्थानों का सौन्दर्यीकरण एवं वृक्षारोपण, हरियाली की व्यवस्था लखनऊ मेट्रो द्वारा कराया जाएगा। इस अवसर पर मेट्रो के प्रबंध निदेशक श्री कुमार केशव, निदेशक वर्क्स संजय कुमार, ओएसडी ए0आर0 खान, नगर आयुक्त डा. इन्द्रमणि त्रिपाठी एवं कई पार्षद उपस्थित थे।

अपने दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे राहुल गांधी

लखनऊद्य लोकसभा चुनाव से पहले अपनी तैयारियों को धार देने में जुटे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को दो दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे। इससे पहले लखनऊ हवाईअड्डे पर कांग्रेस नेताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इसके बाद राहुल यहां से सीधे अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिये सुबह से ही चौधरी चरण सिंह हवाईअड्डे पर कांग्रेस नेताओं की भारी भीड़ थी। खुद प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर वहां मौजूद थे।

राहुल गांधीउनके अलावा पूर्व सांसद प्रमोद तिवारी, पूर्व केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद, पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व सांसद अन्नू टंडन, पूर्व

विधायक प्रदीप माथुर, प्रवक्ता के.के. पांडे, ब्रिजेंद्र सिंह आदि कांग्रेस अध्यक्ष का स्वागत करने वालों में शामिल थे।

कांग्रेस अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी बुधवार को अमेठी के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। इस दौरान वह कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनमें नया जोश भरने की कोशिश करने के साथ ही किसानों व व्यापारियों की समस्याएं भी सुनेंगे।

जिलाध्यक्ष योगेन्द्र मिश्र ने कहा कि दो दिवसीय दौरे के दौरान राहुल तालाखजुरी के पास मुकुटनाथ इंटर कालेज में किसानों के साथ चौपाल करेंगे। नरैनी गांव जाकर शहीद जवान अनिल मौर्या के परिजनों से मिलेंगे। इसके बाद अपराह्न तीन बजे राहुल दिल्ली के लिए रवाना हो

प्रधानमंत्री आवास योजना में ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली का लगाया आरोप

सीतापुर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चेतावनी देते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार या धन उगाही की शिकायत मिली तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने कहा था कि इस योजना के तहत प्रदेश में लाखो गरीबों को लाभ मिलेगा। उन्होंने ग्राम प्रधान और अधिकारियों को आगाह करते हुए उन्हें सतर्कता बरतने की सलाह भी दी थी। लेकिन सीतापुर की तहसील सीधोली के अन्तर्गत अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम बेडसापुर में प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ग्राम प्रधान पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है।

जनपद के किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के साथ नहीं दिया जाता शौचालय व्यवस्था का लाभ

सिंधौली तहसील के अंतर्गत ग्राम बेडसापुर के लाभार्थियों ने प्रधान मंत्री आवास योजना दिलाने के एवज में ग्राम प्रधान जुगुलकिशोर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया बेडसापुर के ग्रामीण राम खेलावन,पुत्र पाल,एवं राजु, पुत्र मनोहर,मालती, पति नन्हा, व, गोमती देवी, ने मीडिया टीम को बताया कि ग्राम प्रधान जुगुलकिशोर ने प्रधानमंत्री आवास दिलाने के एवज हम लोगो से 10 से 15 हजार रुपये ले लिए। यही नहीं ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि ग्राम प्रधान ने कहा कि ये पैसा ऊपर के अधिकारियो को भेजा जायेगा। आरोप है कि अभी ग्रामीणों की मजदूरी का भुगतान नहीं हुआ है।

अपात्रों को आवासो का आवंटन करने का आरोप

तमाम प्रयासों के बावजूद प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार रुक नहीं पा रहा है। अपात्रों को आवासों का आवंटन और उगाही की शिकायतें आम हैं। जिले की कई पंचायतों में धांधली की

गांव में दर्शन करने के लिए खंभों पर लगा रखा है ट्रांसफार्मर

अटरिया–सीतापुर क्षेत्र के मुराऊखेडा गांव में ट्रांसफॉर्मर केवल सो पीस बन कर रह गया है मुराऊखेडा गांव में ट्रांसफार्मर जलकर बर्बाद हो गया है। जिससे मुराऊखेडा गाव की आबादी अंधेरा मे पसरा हुआ है. मुराऊखेडा गांव की आबादी को देखते हुए विद्युत विभाग के द्वारा एक ट्रांसफार्मर लगाया गया था। जिससे पूरे गांव में बिजली मिलती थी।बीते आठ दिनो से ट्रांसफार्मर के जलते ही मुराऊखेडा गांव की आबादी चिराग युग में पहुंच गया है। बताते चलें कि कि बीते आठ दिनो से ट्रांसफॉर्मर जला हुआ है और इस भीषण गर्मी में विद्युत विभाग उपभोक्ताओं की परीक्षा ले रहा है.

जिससे आधी आबादी भीषण गर्मी व अंधेरे में रहने को मजबूर हैं. उपभोक्ताओं को काफी दिक्कतो कई सामना करना पड़ रहा है. शाम होते ही आधी आबादी अंधेरे में डूब जाती है और आधी आबादी रोशनी से गुंजायमान रहती है. अटरिया क्षेत्र के मुराऊखेडा गांव में रखा ट्रांसफॉर्मर केवल सो फीस बन कर रह गया है अजय कुमार, विजय तिवारी,मयंक तिवारी,कलेट्टर ,रिषू पाण्डे,आर पी मिश्रा,राधेश्याम, सन्तोष आदि ने ट्रांसफॉर्मर सही कराने की मांग की है।

विधुत विभाग सिधौली के जेई मिथलेश कुमार यादव ने बताया कि यह सूचना हमारे संज्ञान में है गुरुवार को शाम तक ट्रांसफार्मर रखवा दिया जाएगा।

फोन रिकार्डो से निकलेगा फर्जी मुठभेड़ों का सच : रिहाई मंच

लखनऊ। रिहाई मंच ने पीयूसीएल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा योगी सरकार से एनकाउंटर के मामलों में जवाब तलब किए जाने का स्वागत किया। जवाब तलब किए जाने बाद डीजीपी ओपी सिंह के बयान की मुठभेड़ों की रणनीति में कोई बदलाव नहीं पर मंच ने कहा कि डीजीपी योगी सरकार में फर्जी मुठभेड़ों में मारे गए लोगों की जाति को सार्वजनिक कर दें सब रणनीति सबके सामने आ जाएगी। एडीजी कानून व्यवस्था आनंद कुमार के बयान कि मुठभेड़ में मारे गए 59 मामलों में 25 की न्यायिक जांच पूरी और 23 मामलों में पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगाई है जिसमें से 16 को कोर्ट स्वीकार भी कर चुकी है पर मंच ने सवाल खड़े किए हैं। मंच ने आजमगढ़ के फर्जी मुठभेड़ों मे मारे गए छह लोगों के केसों की स्थिति जारी करते हुए इस जांच प्रक्रिया पर सवाल उठाया है। पुलिस की फाइनल रिपोर्टों पर सवाल करते हुए कहा कि जो पुलिस एफआईआर की कापी और पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे रही है वो फाइनल रिपोर्ट में क्या रिपोर्ट लगाएगी यह तो योगी जी को ही मालूम होगा जिन्होंने श्ठोक देनेश वाले बयान देकर अपराधी पुलिस वालों के मनोबल को बढ़ाया और अपराधी के नाम पर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों की हत्याएं की गई। फर्जी मुठभेड़, रासुका और भारत बंद के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न को लेकर रिहाई मंच ने आजमगढ़ का दौरा किया। प्रतिनिधिमंडल में मसीहुद्दीन संजरी, तारिक शफीक, शाहआलम शेरवानी, सालिम दाउदी के साथ लक्ष्मण प्रसाद, अनिल यादव और राजीव यादव शामिल थे।

मानवाधिकार आयोग की जांच के संबन्ध में पूछे जाने पर मुकेष राजभर के भाई सर्वेष राजभर बताते हैं कि उन्हें किसी भी जांच की कोई सूचना नहीं मिली और न ही उन्होंने कोई बयान ही दर्ज करवाया है। जांच के संबन्ध में ठीक यही बात जय हिंद यादव के पिता षिवपूजन यादव बताते हैं कि उनका कोई बयान नहीं दर्ज किया गया है। न तो उन्हें अब तक एफआईआर की कापी ही दी

गई है और न ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट। वे बताते हैं कि इसके लिए उन्होंने काफी प्रयास किया पर उन्हें अब तक नहीं मिल सका। वहीं फर्जी मुठभेड़ में मारे गए मोहन पासी के पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है जिसके चलते उनकी मां गांव में नहीं रहती हैं। छन्नू सोनकर के भाई झब्बू सोनकर ने एसडीएम सदर आजमगढ़ की अनुपस्थिति में उनके निर्देषानुसार उनके कार्यालय में लिखित बयान दिया। राम जी पासी के भाई दिनेष सरोज ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपना बयान दर्ज करवाया है। राज्य मानवाधिकार आयोग से सूचनार्थ पत्र प्राप्त हुआ पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई या जांच के बारे में उन्हें नहीं मालूम। यहां गौरतलब है कि मानवाधिकार आयोग आजमगढ़ के जय हिंद यादव, राम जी पासी, मुकेष राजभर और इटावा के आदेष यादव की फर्जी मुठभेड़ की जांच कर रहा है। पर जिनके मामलों की जांच हो रही है उन्हें ही इसके बारे में कुछ नहीं मालूम। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा फर्जी मुठभेड़ों पर की जा रही जांचों की स्थिति को जानने के लिए रिहाई मंच प्रतिनिधिमंडल मेहनगर थाने के पास के हटवा खालसा गांव पहुंचा। रामवृक्ष यादव, जिनके दो लड़कों विनोद यादव और पंकज यादव को अन्य युवकों के साथ अलग–अलग जगहों से उठाया गया था और सवाल उठने पर विनोद यादव को पुलिस ने छोड़ दिया और पंकज के पैरों में गोली मारकर फर्जी मुठभेड़ दिखाई थी, को 24 जून को बयान दर्ज कराने के लिए एसएसपी कार्यालय बुलाया गया था। जहां उन्होंने जाकर अपना बयान दर्ज करवाया। उन्होंने अपने बेटों की अवैध हिरासत और फर्जी मुठभेड़ के सवाल को अपने बयान में दर्ज करावाया है। पंकज की मां आज भी 100 नंबर का हवाला देते हुए कहती हैं कि लगातार फोन किया गया पर पुलिस वाले बताए नहीं और सुबह हमारे लड़के के पैर में गोली मारकर बदमाष कह रहे हैं। हमारे लड़के पर कोई मुकदमा नहीं है। वहीं पूर्व में जिला पंचायत सदस्य रह चुके रामवृक्ष यादव कहते हैं बेटे की राजनीतिक पहचान के वजह से वह पुलिस के निषाने पर आ गया। आज भी पंकज यादव, अजय यादव, राजतिलक सिंह, सुनील यादव जैसे कई लड़के जिनके पैर में पुलिस ने बोरी बांधकर फर्जी मुठभेड़ दिखाकर गोली मारी जेल में कैद हैं। जहां उनका सही से इलाज नहीं हो पा रहा है। गौरतलब है कि पुलिस ने बड़े पैमाने पर फर्जी मुठभेड़ों में लोगों के पैरों में बोरी बांधकर गोली मारी जिसकी वजह से उनके घुटने खराब हो गए हैं। सरायमीर आजमगढ़ के पास पवई लाडपुर गांव के रहने वाले अजय यादव जिन्हें पिछले दिनों फर्जी मुठभेड़ में पैर में गोली मारी गई थी की मां कहती हैं कि बहुत मुष्किल हो गई है। उनके पास इतना पैसा नहीं की वो जेल में हाल–चाल लेने जा सकें इलाज तो बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इन लड़कों का ईलाज एक गंभीर सवाल बन गया है। वहीं परिजनों का पूर्व में आजमगढ़ के एसएसपी रहे अजय साहनी पर आरोप है कि इलाज सही से न हो पाए वे इसकी लगातार कोषिष करते थे जिससे लोगों को पीड़ा हो और इनफेक्षन से उनका पैर काटना पड़ जाए। यह पुलिस के आपराधिक और अमानवीय क्रूर चेहरे को सामने लाता है। एसओजी के अरविंद यादव की फर्जी मुठभेड़ों में सबसे अधिक आपराधिक भूमिका रही है। अरविंद ने कन्धरापुर थाने पर रहते हुए संजरपुर के आफताब और मोनू को उठाया पर सूचना सार्वजनिक होने के बाद उन्हें छोड़ा। आजमगढ़ में अरविंद को खास तौर पर मुठभेड़ के नाम पर हत्याएं करने के लिए रखा गया है। इसीलिए मीडिया में आई रिपोर्टों में राकेष पासी की फर्जी मुठभेड़ में हत्या की वारदात में बयान एसओजी की तरफ से अरविंद का ही आया जबकि उन्हें कुछ ही दिनों पहले कंधरापुर थाने का चार्ज दिया गया था। इस फर्जी मुठभेड़ों के खेल में बड़े पैमाने पर जान के बदले धन उगाही की गई। आज तक जयहिंद यादव, राकेष पासी और कई ऐसे परिवार है जिनमें से कई के पास एफआईआर तो किसी के पास पोस्टमार्टम तक की रिपोर्ट नहीं है। जबकि उसको पाने का उन्हें अधिकार है। जो एडीजी के उस बयान पर सवाल उठाता है कि पुलिस ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फाइनल रिपोर्ट लगाने वाली पुलिस अगर सच्ची है तो एफआईआर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने में उसे क्यों डर लग रहा है।

मनकामेश्वर मंदिर पहली बार देगा इफ्तार पार्टी, तैयारियां जोरों पर...

लखनऊ। पहली बार मनकामेश्वर मंदिर में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए तैयारिया जोरो पर है। रविवार शाम 10 जून को शिव जी के इस मंदिर में पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जाएगा। इफ्तार में मंदिर से ही तीन बावर्ची आने वाले रोजेदारों के लिए खाना बनाएंगे। खाने में कॉफी,ब्रेड,कटलेट,केला,आलू कटलेट और फल दिया जाएगा।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मनकामेश्वर मंदिर की महिला महंत दिव्या गिरी ने बताया कि इस इफ्तार पार्टी को पूरी तरह से भव्य बनाए जाने की तैयारी है।इसके लिए शिया और सुन्नी समुदाय के धर्म गुरुओं को न्योता भेजा जा चुका है।

पहली बार इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है,तो आशा हा कि ये एतिहासिक साबित होगा और शहर की सामंजस्यपूर्ण परंपराओं को बहाल करेगा।बता दे मनकामेश्वर मंदिर काफी साल पुराना मंदिर है और इसके बारे में कहा जाता है यहाँ हर दुआ पूरी होती है। मंदिर में इफ्तार आयोजन से मुस्लिम समाज भी उत्साहित है।

जानकारी के लिये बता दें कि कुछ ही रोज पहले अयोध्या के एक प्राचीन मंदिर में हिन्दु धर्म गुरूओं द्वारा इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, अयोध्या में साधुओं ने ऐलान भी किया था कि अब वे हर साल रमजान के महीने में इफ्तार पार्टी का आयोजन करेंगे।

ये किसी ऐतिहासिक बात से कम नहीं है कि शिव जी के मंदिर में पहली बार इफ्तार

तस्करी करने वाले गिरोह के दो सदस्य गिरफ्तार

लखनऊ। उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने अवैध शस्त्रों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक महिला एवं पुरूष सदस्य को गिरफ्तार कर उनसे अवैध असलहा बरामद किया। पुलिस के आधिकारिक सूत्रों ने बुधवार यहां बताया कि मऊ के थाना घोसी निवासी मो0 दानिश और नन्नहीन को स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने गिरफ्तार कर उनके पास से एक अवैध पिस्टल , मैगजीन , एक मोबाइल और 350 रूपये नकद बरामद किया। गिरफ्तार अभियुक्तों के खिलाफ आर्म्स एक्ट सहित विभिन्ना धाराओं में मुकदमा दर्ज करके आगे की कार्रवाई स्थानीय पुलिस द्वार की जारही है।

तहसील में लेखपालों का आठ सूत्री मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रांतीय नेतृत्व के आवाहन पर संघ की लंबित मांगों को पूर्ण कराने के संदर्भ में आज दिनांक 4–07–2018 को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की उपशाखा लहरपुर जिला सीतापुर के द्वारा तहसील लहरपुर के प्रांगण में आंदोलन के रूप में पूर्ण कार्य बहिष्कार कर दूसरे दिन भी धरना प्रदर्शन प्रातः 10रू00 बजे से 4रू00 बजे तक जारी रहा धरना स्थल पर सभा की अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष मनमोहन शुक्ला के द्वारा तथा संचालन तहसील मंत्री गौरी शंकर पाल द्वारा किया गया सभा में संघ की 8 सूत्रीय मागो यथा वेतन, उच्चीकरण वेतन, विसंगति पेंशन, विसंगति भत्तों में बढ़ोतरी, राजस्व निरीक्षक सेवा नियमावली 2017 को कैबिनेट से पारित कराना लैपटॉप व स्मार्टफोन दिलाये जाने, प्रोन्नत किए जाने तथा आधारभूत सुविधाएं एवं संसाधन उपलब्ध कराए जाने जैसे मांगों पर चर्चा की गई आज की बैठक में पूर्व मंत्री प्रदीप वर्मा, छोटेलाल, अमित श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, अमित कटियार, अवनीश यादव, रामपाल आर्य, अवधेश कुमार, श्री ओम, अंजू यादव, आयशा बानो, प्रीति पाल, आदि लेखपाल मौजूद रहे ।

विवेचक को आवाज का नमूना दें मुलायम : कोर्ट

लखनऊ। आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव द्वारा कथित फोन पर धमकी देने के मामले में अब तक मुलायम सिंह द्वारा आवाज का नमूना न दिये जाने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आनंद प्रकाश सिंह ने विवेचक को 20 दिन का समय देते हुए मुलायम सिंह यादव को निर्देश दिया है कि वह आवाज का नमूना देने में विवेचक को सहयोग करें अन्यथा यह अवधारणा की जाएगी कि प्रश्नगत आवाज मुलायम सिंह की है।विवेचक अनिल कुमार यादव ने आख्या प्रस्तुत कर आवाज का नमूना शीघ्र प्राप्त कर कार्रवाई किये जाने का आश्वासन दिया, जिस पर अदालत ने उन्हें 20 दिन का समय प्रदान करते हुए मुलायम सिंह को निर्देश दिया है कि वह वायस सैम्पुल लेने में विवेचक को पूर्ण सहयोग करें। अदालत ने इस मामले में 20 अगस्त 2016 को विवेचक को निर्देश दिया था कि वह आरोपी मुलायम सिंह यादव की आवाज का नमूना लेकर मिलान करें, लेकिन आदेश का अनुपालन अभी तक नहीं हो सका है।

किंग जार्ज चिकित्सा विविद्यालय के ट्रामा सेंटर में मरीज की मौत पर हंगामा

लखनऊ। किंग जार्ज चिकित्सा विविद्यालय के ट्रामा सेंटर में सर्जरी के बाद सत्रह वर्षीय कि शोर की मौत के बाद हंगामा किया। मरीज की मौत पर परिजनों ने डाक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ट्रामा सेन्टर में कर्मचारियों व गार्ड से हाथापाई कर जमकर हंगामा किया। उन्होंने आरोप था कि डाक्टर उनसे इलाज के लिए दो लाख रुपये की मांग कर रहे थे। रुपये न देने पर इलाज में लापरवाही मौके पर पुलिस ने आकर मामला शांत कराया।आलमबाग निवासी आकाश को पेट में तेज दर्द की शिकायत थी। परिजनों ने उसे दो जुलाई को ट्रामा सेन्टर के इमरजेंसी मेडिसिन में भर्ती कराया। डाक्टरों ने उसके पेट में कुछ संक्रमण बताया था, जिसके कारण उसकी एक आंत फट गयी थी। इस कारण उसे सर्जरी करने की सलाह दी गयी थी। परिजनों का आरोप है कि सर्जरी के लिए अनुमति देने के बाद डॉ. हैदर अब्बास व प्रो. अभिनव अरूण सोनकर के निर्देशन में मरीज का ऑपरेशन किया गया था। परिजनों का कहना है कि सर्जरी के बाद डाक्टरों ने आश्वासन दिया कि वह ठीक हो जाएगा, उसकी हालत लगातार बिगड़ती गयी और आज को आकाश की मौत हो गयी। मौत से आक्रोशित परिजनों ने वार्ड में ही हंगामा करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों व गार्ड ने जब उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो उन्होंने गार्ड व कर्मियों से मारपीट की तथा जमकर हंगामा काटा। इस पर डाक्टरों ने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। ट्रामा सेंटर पहुंची पुलिस ने मौके पर आकर हंगामा कर रहे परिजनों ने बाहर निकाल दिया। इसके बाद उन्होंने ट्रामा सेन्टर के गेट पर परिजनों ने काफी देर तक हंगामा किया। उनका आरोप था कि डाक्टर उनसे दो लाख पयों की मांग कर रहे थे, पैसा न मिलने पर उन्होंने ठीक तरह से ऑपरेशन नहीं किया, जिससे मरीज की मौत हो गयी।

गीता वर्मा होंगी शामली की बीएसए

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने आज बारह बेसिक शिक्षा अधिकारियों के तबादले कर दिये हैं। उत्तर प्रदेश शैक्षणिक सामान्य शिक्षा संवर्ग सेवा समूह ख उच्चतर में कार्यरत अधिकारियों में हरीश चन्द्र नाथ को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बांदा बनाया गया है, जबकि जयसिंह को वाराणसी का बीएसए बनाकर भेजा गया। हेमंत राव को हरदोई का बीएसए बनाया गया है। संतोष कुमार देव पांडेय को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी देवरिया बनाया, जबकि विनय कुमार को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी के पद पर भेजा गया है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बरेली की वरिष्ठ प्रवक्ता श्रीमती गीता वर्मा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी शामली के पद पर भेजा गया है। इसी प्रकार वाराणसी के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जयप्रताप सिंह को डायट रायबरेली में वरिष्ठ प्रवक्ता बनाया गया है। इसके अलावा रमाकांत वर्मा को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गोंडा बनाया गया।

करोड़ों का चूना लगाकर फरार हुई फर्जी कम्पनी

दोगुने पैसे की लालच में सौंपी अपनी गाढ़ी कमाई,

लखनऊ। मऊ जिले में एक सनसनी खेज मामला सामने आया है। जहां एक जेकीवी नाम की कम्पनी पैसा दूना करने के नाम पर जनता से पैसा जमा कराया और जब समय पूरा हो गया, तो जनता ने पैसा माँगा तो पैसे देने में आना कानी कर कम्पनी फरार हो गई।

इस मामले की सूचना जब जनता को हुई, तो उनके पाव तले जमीन खिसक गई। वहीँ कुछ पीड़ितों ने शहर कोतवाली में कम्पनी और इसके डायरेक्टर राजेश सिंह के खिलाफ धारा 419, 420 के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।

मुकदमा दर्ज के बाद भी पुलिस फर्जी कम्पनी चलाने वाले राजेश सिंह और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार करने के बजाय मौन है। वहीँ न्याय के लिए पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। बावजूद इसके न्याय नही मिल रहा है।

आपको बता दे की शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गाजीपुर तिराहे पर जेकीवी कम्पनी स्थित थी। जिसके डायरेक्टर राजेश सिंह है। अब देखना ये होगा की करोड़ो रूपये लेकर भागने वाली कम्पनी से गरीब जनता का पैसा कौन वसूल करवाएगा।

वहीँ इस पूरे मामले में अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया की मुकदमा दर्ज के बाद से ही अभियुक्त फरार हो गया है। जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जायेगा।

इस मामले में पीड़ित ह्रदय नारायण राय ने आरोप लगाया है कि जेकीवी कम्पनी थी, जिसके डायरेक्टर राजेश सिंह है और मऊ जिले के निवासी हैं। ये पैसा दूना करने के लिए हम सभी लोगों से पैसा जमा करवाया था और समय होने पर जब हम लोग पैसा मांगने गये तो पैसे देने में आना–कानी करने लगे।

उसके कम्पनी बंद कर फरार हो गये। हम लोगों ने इस मामले में कोतवाली में मुकदमा भी दर्ज कराया है। लेकिन पुलिस कार्यवाई नहीं कर रही है। वहीँ एक गरीब किसान ने बताया कि हमारा 2।5 लाख रूपये जमा है और कम्पनी लेकर फरार हो गई।

लक्ष्मण मूर्ति लगवाने की मांग को लेकर अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद ने दिया धरना

लखनऊ। लखनऊ में टीले वाली मस्जिद के सामने पार्क में भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण की मूर्ति लगाने को लेकर चल रहे विवाद में प्रवीण भाई तोगड़िया का संगठन अंतरराष्ट्रीय हिन्दू परिषद (अंहिप) भी कूद गया है। बुधवार को परिषद के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्मण मूर्ति लगवाने की मांग को लेकर हजतरगंज स्थित जीपीओ पार्क में धरना दिया। परिषद के प्रवक्ता आशीष अवस्थी ने कहा कि टीवी डिबेट में बहस के दौरान मौलाना शाजिद रशीदी ने कहा था कि मूर्ति नहीं लगने देंगे। भले उसके स्थान पर किसी जानवर की मूर्ति लगे। राज्यपाल राम नाईक के नाम से ज्ञापन प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा गया है, जिसमें मौलाना शाजिद रशीदी के खिलाफ रासूका लगाने की मांग की गयी है।

उन्होंने कहा कि टीले वाली मस्जिद के स्थान पर ही लक्ष्मण की मूर्ति लगनी चाहिए, क्योंकि उस स्थान पर पहले मंदिर था। इस मुद्दे पर प्रवीण भाई तोगड़िया से वार्ता हुई है। मांगों को प्रशासन व नगर निगम नहीं मानता है तो परिषद आंदोलन करेगा। अंत में अवध प्रांत से जुड़े कार्यकर्ताओं ने अपना मांग पत्र प्रशासनिक अधिकारी को सौंपा।

निजी हास्पिटल पर छापा एक लाख की दवाएं जब्त, डाक्टर हिरासत में

लखनऊ। खाद्य सुरक्षा औषषि प्रशासन (एफएसडीए) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राजाजीपुरम स्थित सेठी हॉस्पिटल में बृहस्पतिवार को छापा मारा। छापे में अधिकारियों ने जांच पड़ताल करने पर हॉस्पिटल में लगभग एक लाख पये से ज्यादा की दवाएं जब्त कीं है। जब्त दवाओं में काफी मात्रा में प्रतिबन्धित दवाएं व नारकोटिक्स की दवाएं भी शामिल हैं। आरोप है कि बीयूएमएस की डिग्री के साथ मरीजों का एलोपैथ से इलाज करने तथा बगैर ड्रग लाइसेंस के इतनी बड़ी मात्रा में क्लीनिक में दवाएं रखने तथा बेचने के आरोप में टीम ने डॉ. प्रदीप कुमार सेठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी गयी है। उन्हें पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। जांच में यह भी पाया गया कि डा. सेठी ने स्वास्य विभाग में हॉस्पिटल का पंजीकरण भी नहीं कराया था। असिस्टेंट कमिश्नर पीके मोदी के निर्देश पर मारे गए छापे में टीम की अगुवाई कर रहे ड्रग निरीक्षक रमा शंकर, माधुरी सिंह, व सुनील कुमार रावत ने सेठी हॉस्पिटल की जांच पड़ताल की। जांच में पाया गया कि हॉस्पिटल पर बड़ी मात्रा में एलोपैथ की दवाएं रखी हुई थी। दवाओं की जांच पड़ताल में कई प्रतिबन्धित दवाएं भी बरामद हुई तथा कई नारकोटिक्स की दवाएं भी थीं, जिन्हें बेचना तथा खरीदना मना है।

शादी के 12 साल बाद मूल धर्म में वापस लौटी युवती

अलीगढ़। करीब 12 साल पहले कथित तौर पर 'लव जेहाद' की शिकार एक युवती ने आज यहां वैदिक रीति रिवाज से अपने मूल धर्म में वापसी की।

हिन्दू महासभा के प्रवक्ता अशोक पांडेय ने बताया कि 12 साल पहले वन्दना चौहान (30) ने धर्म परिवर्तन कर एक मुस्लिम युवक से विवाह किया था हालांकि धोखे से बनाया गया संबंध ज्यादा दिनो तक नहीं चल सका और युवती ने दोबारा अपने मूल धर्म में वापसी की।

डॉ पांडेय ने कहा कि वन्दना उर्फ सना कल उनके पास आई थी। युवती की आप बीती सुनकर उन्होने महासभा में महासचिव पत्नी पूजा पांडे के साथ एसएसपी से मुलाकात की और वन्दना की तहरीर पर सिविल लाइन्स थाने में जेठ जमशेद खां, देवर जिया शरीफ खां, ससुर मोहम्मद शरीफ खां सास शहरबानों व पति शुएब शरीफ के खिलाफ शारीरिक उत्पीडन, बलात्कार व धोखा देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है।

थाना सिविल लाइन्स के प्रभारी निरीक्षक जावेद खॉ ने पुष्टि करते हुये कहा कि धारा 376,420,504,506 व दहेज एक्ट के तहत रिपोर्ट दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है।

बन्दना उर्फ सना की तहरीर में उल्लेख किया गया है कि शुएब करीब 12 वर्ष पहले कबीर चौहान बनकर हिन्दू रीति रिवाज से शादी करके अपने मकान सईदवाडा बाबरीमंडी में ले गया जहॉ सास ससुर पति जेठ ने बन्दना चौहान से नाम बदल कर सना शुएब करके मुस्लिम धर्म के अनुसार निकाह किया उससे दो पुत्रों को जन्म दिया है।

शादी करने के बाद से वह पति, ससुर, जेठ, देवर आदि के उत्पीडन की शिकार होती चली आ रही है। उसे विदेश में बेचने के लिए पासपोर्ट बनवा दिया है। उसका पति शुएब दूसरी शादी करना चाहता है जिसका विरोध किए जाने पर उसका कपडा जेवर छीन कर घर से निकाल दिया है।

ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में केजीएमयू में तीन बच्चों की मौत

लखनऊ। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कालेज में आईसीयू और इंसेफलाइटिस के मरीजों के लिए बनाए गए वार्ड में आक्सीजन सप्लाई ठप होने से 30 बच्चों की पिछले दिनों मौत हो गई थी। इस कांड ने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया था। इस बार राजधानी लखनऊ के चौक इलाके में स्थित किंगजार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (केजीएमयू) में डॉक्टरों की लापरवाही से 3 मासूम बच्चों की जान चली गई। मासूमो की मौत से केजीएमयू में हड़कंप मच गया। मासूमों की मौत से उनके परिजनों का रो–रो कर बुरा हाल है।

जानकारी के मुताबिक, मामला केजीएमयू के ट्रामा सेंटर का है। यहां परिजनों ने आरोप लगाते हुए बताया कि एक ऑक्सीजन सिलेंडर लगाकर 4 बच्चों को ट्रॉमा सेंटर से बाल विभाग शिफ्ट करने के लिए ले जाया जा रहा था। इसी दौरान हुई 3 बच्चों की मौत हो गई। परिजनों ने एक एक कर बच्चों को बाल विभाग में शिफ्ट करने की बात कही थी। लेकिन वार्ड बॉय एक साथ 4 बच्चों को शिफ्ट कर ले जा रहा था। आरोप है कि बाल विभाग वार्ड बॉय की जिद के आगे 3 मासूमो की जाने चली गयी। आक्सीजन के अभाव में तीन मासूमों के दम तोड़ने के मामले में स्वास्थ्य महकमा ही नहीं बल्कि केजीएमयू खुद को पाक–साफ बता रहा है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सीएमओ ने जांच कराने की बात कही है।

लखनऊ जं. पर घंटों बिजली गुल, हंगामा

लखनऊ। लखनऊ जंक्शन पर गुरुवार दोपहर कई घंटे तक बिजली गुल होने से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे नाराज यात्रियों ने स्टेशन पर हंगामा किया। काफी देर तक जब बिजली नहीं आयी तो यात्रियों ने स्टेशन निदेशक का घेराव कर लिया। काफी देर तक चले हंगामे के बाद स्टेशन निदेशक महावीर सिंह ने यात्रियों को समझा–बुझाकर शांत कराया। स्टेशन निदेशक के हस्तक्षेप के बाद विद्युत आपूतर्ि बहाल हुई। इसके बाद यात्रियों को राहत मिली। लखनऊ जंक्शन पर बिजली गुल होने से पंखे, विश्रामालय, प्रतीक्षालय, वाईआईपी लाउंज के एसी बंद हो गया। गर्मी व उमस के बीच प्लेटफार्मो पर ट्रेनों का इंतजार कर रहे मुसाफिरों को पसीना बहाना पड़ा। रेलवे की व्यवस्था से खफा यात्रियों ने इसकी शिकायत स्टेशन मास्टर के यहां दर्ज करायी।

शूटर बिटिया के खर्चे के लिए पिता ने भैंस बेचने की ठानी

लखनऊ। मेरठ के मवाना निवासी 19 साल की प्रिया का चयन जर्मनी में 22 जून को होने वाली ISSF जूनियर वर्ल्ड कप में हुआ है। भारत की तरफ से 6 प्रतियोगियों का चयन हुआ है, जिसमे प्रियंका का चौथा नम्बर है। प्रिया का चयन 50 मीटर राइफल कैटेगरी में हुआ है।

प्रिया के पिता एक गरीब मजदूर हैं परिवार की माली हालत ठीक ना होने के चलते प्रिया के इस प्रतियोगिता में भाग लेने पर अभी प्रश्नचिन्ह लगा हुआ था। वैसे तो सरकार विदेश में जाकर खेलने वाले प्रतियोगी का खर्चा तो उठाती है।

लेकिन क्वालीफाई करने वाले टॉप तीन खिलाड़ियों का ही और प्रिया की रैंक चौथे नंबर पर है। पिता ने बेटी के खर्च के लिए घर मे बंधी भैस को भी बेचने की भी तैयारी कर ली। इसके बाद भी खर्चा पूरा होता नहीं दिखाई दे रहा। प्रिया का परिवार सरकार से मदद की गुहार लगा रहा है।

नगर निगम की डोर टू डोर हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू

लखनऊ। नगर निगम इस महीने से डोर टू डोर हाउस टैक्स जमा करने की सुविधा शुरू करने जा रहा है। इस सुविधा के शुरू होने के बाद घर बैठे भवन कर, जलकर व सीवर कर जमा कर सकेंगे। नगर निगम के कर्मी हैंड हेल्ड मशीन लेकर घर पहुंचेगे। भवन स्वामी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के जरिये टैक्स जमा कराएंगे और रसीद भी देंगे। 110 वाडरे में से अभी 110 मशीनें आ चुकी हैं। 16 मशीने पहले से निगम के पास हैं। गुरुवार को नगर निगम में निजी बैंक एचडीएफसी ने मशीन का प्रस्तुतिकरण किया। मौजूदा समय में भवन स्वामियों को हाउस टैक्स सहित अन्य बिलों का भुगतान नगर निगम क'' कैश काउंटरों पर करना पड़ता है। इस व्यवस्था में खासतौर पर नौकरी पेशा, सीनियर सिटीजन व महिलाओं को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अपने सभी काम छोड़कर बिल जमा करने के लिये पूरा दिन बर्बाद हो जाता है।ऑन लाइन टैक्स जमा करने की सुविधा भी दी गयी है मगर इसमें कई प्रकार की परेशानी आ रही हैं। अब नगर आयुक्त के सामने बैंक के प्रतिनिधि से मशीन को चलाकर दिखाया। कार्ड के जरिए भुगतान होने के बाद भवन स्वामी के मोबाइल पर मैसेज व लिंक भी आयेगा। टैक्स वसूली बढ़ाने के लिये नगर निगम जल्द ही लोगों को हाउस टैक्स जमा करने क'' लिए एक और सहूलियत देने जा रहा है। गुरुवार को इस लिंक के जरिये पूर्ण बिल का ेपट्र कराया जा सकेगा। नगर आयुक्त डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया पानी और सीवर टैक्स क'' बिलों क'' अलावा व्यवसायिक संपत्तियों का किराया और नगर निगम से संबंधित अन्य भुगतान भी इसी माध्यम से जमा कराने की सुविधा देने का प्रयास किया जायेगा। हाल ही में नगर निगम ने विभिन्न टैक्स के भुगतान करने की कैशलेस व्यवस्था भी की है। अभी टैक्स संबंधी डिमांड भेजी जाती है। करीब 30 फीसदी लोग ही टैक्स जमा करते हैं, बाकी के 70 फीसदी बिल न भेजने अथवा टैक्स ज्यादा होने को लेकर बिल ही जमा कर रहे हैं। नगर निगम ने हाउस टैक्स सॉफ्टवेयर की एक्सेस

सम्पादकीय

पुलिस सुधार का अदालती निर्देश

सर्वोच्च न्यायालय ने पुलिस सुधार के लिए जो दिशा–निर्देश जारी किए हैं, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। न्यायालय ने पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति से संबंधित कोई भी नियम या राज्य का कानून स्थगित रखने के अपने आदेश में ही कहा है कि पुलिस नियुक्तियों के बारे में कानून बनाने वाले राज्य इस आदेश में सुधार के लिए न्यायालय आ सकते हैं। वर्तमान दिशा–निर्देश में सबसे महत्त्वपूर्ण है पुलिस महानिदेशकों, पुलिस आयुक्तों की नियुक्ति। मसलन, शीर्ष अदालत ने साफ कहा है कि किसी भी पुलिस अधिकारी को कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक या पुलिस आयुक्त नियुक्त न करे। यानी जो नियुक्त होगा वह पूर्ण होगा। इस संबंध में नियम बदल दिए गए हैं। अब राज्यों को वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की सूची संघ लोक सेवा आयोग को भेजनी होगी, जिनमें वह तीन अधिकारियों की सूची तैयार कर राज्य सरकारों को भेज देगा। राज्य इनमें से ही किसी एक की नियुक्ति के लिए बाध्य होंगे। राज्यों को यह भी ध्यान रखना होगा कि उन अधिकारियों के पास पर्याप्त कार्यकाल बचे हों। वस्तुतरू यह वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की नियुक्तियों में राजनीतिक मनमानी या हस्तक्षेप को खत्म करने का कदम है। यह शिकायत लंबे समय से रही है कि सरकारें अपने मनमाफिक अधिकारियों की नियुक्तियां करतीं हैं, जिनसे कानून और व्यवस्था हमेशा प्रभावित होता है। प्रकाश सिंह मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 2006 में पुलिस सुधारों पर विस्तृत निर्णय दिया था। दुर्भाग्य से वह आज तक लागू नहीं हो सका है। इसमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को कम–से–कम दो वर्ष का कार्यकाल देने का भी निर्देश था। केंद्र सरकार ने इसमें संशोधन के लिए एक याचिका न्यायालय में डाला हुआ है। इसमें पुलिस महानिदेशकों का कम–से–कम दो साल का कार्यकाल सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने जैसा न्यायायल का निर्देश भी शामिल था। वास्तव में उच्चतम न्यायालय के पूर्व फैसले का मूल उद्देश्य पुलिस पण्राली को समय के अनुरूप स्वायत्त, निष्पक्ष और कार्यक्षम बनाना था। किंतु राजनीति को वह फैसला नहीं सुहाया था। उसमें एक मॉडल प्रारूप भी बना था। उस पर तो किसी राज्य ने विचार तक नहीं किया। सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश के बावजूद राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश उन्हें तत्काल लागू कर देंगी ऐसा नहीं लगता। देखना है कौन–कौन राज्य सरकार पुनर्विचार याचिकाएं लेकर न्यायालय पहुंचतीं हैं। किंतु न्यायालय अपने निर्णय में अब कोई बदलाव करेगा ऐसा लगता नहीं।

हिंसा के रूप में पाशविक समाज

पिछले कुछ वर्षो से भीड़ द्वारा की जा रही हिंसा के रूप में पाशविक सामाजिक प्रवृत्ति का उभार तेजी से हो रहा है। विशेषकर गोरक्षा के नाम पर लोग कानून को अपने हाथमें लेकर महज शक के आधार पर किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने भीड़ की बढ़ती हिंसा और हत्या की घटनाओं पर चिंता जताते हुए कहा है कि गोरक्षा के नाम पर कोईभी व्यक्ति कानून को अपने हाथमें नहीं ले सकता। भीड़ द्वारा की गई हिंसा और हत्या कानून–व्यवस्था की समस्या नहीं, अपराध है, और इसे रोकना राज्यों का दायित्व है। हालांकि भारतीय समाज के सुदूर अंचलों में पहले भी भीड़ द्वारा हिंसा की जाती रही है। खासकर विधवा महिलाओं की संपत्ति हड़पने के लिए उन्हें डायन बताकर हिंसा किए जाने के तमाम मामले प्रकाश में आते थे। लेकिन इस पाशविक प्रवृत्ति का जिस तेजी से उभार हो रहा है, वह किसी भी सभ्य और आधुनिक लोकतांत्रिक समाज के माथे पर कालिख है।

इस तरह की घटनाएं भारतीय समाज की प्रगतिशीलता के दावे को संदिग्ध बनाती हैं। लोकतंत्र द्वारा शासित समाज यदि कानून को अपने हाथ में लेकर फैसले लेने लगे तो लोकतंत्र को भीड़तंत्र में तब्दील होने का खतरा साफतौर पर दिखाई देने लगता है। चिंता और हैरानी की बात है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा करने वाले असामाजिक तत्वों के हौसले इतने बढ़ गए हैं कि अब वे बच्चा चोरी का आरोप लगाकर लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। कुछ लोगों का आरोप है कि हिंसा धर्म और जाति को निशाना बनाकर हो रही है। अगर यह सच है तो इसे

सख्ती से रोकने की जरूरत है क्योंकि इससे सामाजिक विघटन का खतरा है। हालांकि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिएसुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल सभी राज्यों को ठोस कदम उठाने का निर्देश दिया था और साथही सभी जिलों में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को नोडल अफसर नियुक्त करने को कहा था। लेकिन इस निर्देश का पालन नहीं हुआ, जिसके कारण हिंसक घटनाओं का ग्राफ बढ़ता गया। बहरहाल, अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विस्तृत दिशा–निर्देश जारी करेगा। सरकार ने भी सामाजिक हिंसा को बढ़ावा देने वाले संदेशों के प्रसार को तत्काल प्रभाव से रोकने के लिए व्हाट्सएप को चेतावनी जारी की है।

अदालत के फैसले ने खींच दी लक्ष्मण रेखा

पांच सदस्यीय संविधान पीठ का 535 पृष्ठीय सर्वसम्मत फैसला स्पष्टतया मोदी सरकार के खिलाफहै, जो दिल्ली के उपराज्यपाल के तमाम फैसलों को तार्किक ठहराती रही है। यह केजरीवाल की आप सरकार की जीत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अब स्वयं को पीड़ित नहीं बता पाएंगे और न ही अपनी सरकार के प्रदर्शन के लिए उपराज्यपाल पर आरोप नहीं लगा सकेंगे। इस फैसले के आधिकारिक निष्कर्ष यह है कि उपराज्यपाल केवल ''प्रशासक'हैं, और सीमित अर्थो में प्रशासनिक मुखिया हैं। मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले दिल्ली के मंत्रिमंडल की सलाह को मानने को बाध्य हैं। उन्हें अपने तई कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं है। उन्हें मंत्रियों की सलाह या राष्ट्रपति को प्रेषित मामलों पर आए आदेशों के अनुसार चलना है। वह प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। हर मामले में उनकी सहमति की जरूरत नहीं है। वह अपवादस्वरूप स्थितियों में ही मामलों को राष्ट्रपति के पास प्रेषित कर सकते हैं, न कि ''हर दिन' या ''मशीनी अंदाज' में। इसका अर्थ हुआ कि सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले से दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को पलट दिया है, जिसमें कहा गया था कि उपराज्यपाल अपने तई स्वतंत्र हैं, और मंत्रियों की सलाह को मानने को बाध्य नहीं हैं। सच तो यह है कि कोई राज्यपाल/उपराज्यपाल अपने तई कार्य करने को स्वतंत्र नहीं होता। अपने वरिष्ठों के प्रति निष्ठा के मामले में भारतीय राज्यपाल अपने ब्रिटिश पूर्ववर्तियों का अनुसरण करते हैं। इस फैसले के आलोक में बेहतर तो यह हो कि दिल्ली के उपराज्यपाल बोरिया–बिस्तर समेट कर अपना इस्तीफा सौंप दें। लेकिन यह भी है कि भाजपा के राज्यपालों का रवैया भी कांग्रेस के राज्यपालों जैसा ही है। न तो उन्होंने अपने स्तर पर स्वतंत्रता दिखाई है, और न ही आत्मसम्मान। कुछ तो ऐसे हैं जो पार्टी कार्यकर्ताओं की भांति कार्य

करते हैं, और उनके बयान और ट्वीट्स को देखें तो उनमें बेहद पक्षपात और ध्रुवीकरण करने की नीयत दिखाई पड़ती है। जस्टिस दीपक मिश्र ने इस मामले में संवैधानिक विमर्श को ऊंचे पायदान पर पहुंचा दिया है। एक सौ 20 पृष्ठों में संविधानवाद समेत हमारे उदार संवैधानिक लोकतंत्र के बारह बुनियादी सिद्धांतों या संविधान के केंद्रीय विचार के रूप में सीमित अधिकारों की अवधारणा पर रोशनी डाली। भारत के प्रधान न्यायाधीश को साधुवाद देना होगा कि उन्होंने जस्टिस एके सीकरी और जस्टिस एएम खानविलकर के साथ मिलकर 237 पृष्ठों में जोरदार ढंग से अपना मत रखते हुए बहुमत का फैसला दिया। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने प्रधान न्यायाधीश से सहमति जताते हुए कहा कि अनेक देशों में निरंकुशता के चलते लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। ''संवैधानिक नैतिकता' बनाए रखना जरूरी है। उन्होंने चार बुनियादी सिद्धांतों का उल्लेखकिया जिनमें उन्होंने धर्मनिरपेक्ष विचार को भी शामिल किया। जस्टिस अशोक भूषण ने 123 पृष्ठीय मत में फैसले से सहमति जताते हुए प्रतिनिधि सरकार तथा संविधान की सोद्देश्य विवेचना पर बल दिया। उन्होंने कहा कि अदालतों को प्रतिनिधि लोकतंत्र, कानून के शासन तथा संविधान की भावना को पुष्ट करने के लिए तयात्मक व्याख्या करनी चाहिए। उन्होंने उचित ही कहा कि संविधान के मूल को ''संविधान की भावना' तथा अंगीकृत उद्देश्य के आलोक में समझा जाना चाहिए। थॉमस जेफरसन का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को शासितों की सहमति से शक्ति मिलनी चाहिए। अपने फैसले के अंत में इन आदशरे का जिक्र करते हुए उन्होंने दिल्ली के उपराज्यपाल की शक्तियों पर कानून की तरजीह होने की बात कही। किसी संवैधानिक प्राधिकार की निरंकुशता पर तल्ख टिप्पणी की। सच तो यह है कि संवैधानिक पद पर आरूढ़ किसी को भी नहीं बख्शा। पीठों के गठन तथा न्यायाधीशों के चयन में संविधान के उच्च सिद्धांतों और लोकप्रियता के नाम पर ऐसी प्रतिनिधि सरकारें कई दफा सत्तारूढ़ हो जाती हैं जो अल्पसंख्यकों के खिलाफकार्य करती हैं। इस प्रकार उस संवैधानिक करार की भावना को ही चोटिल कर डालती हैं, जिसके आधार पर स्वयं राष्ट्र का निर्माण हुआ है। अलबत्ता, यह जरूर कहा कि प्रतिनिधि सरकार तक सभी की पहुंच होनी चाहिए और ऐसी सरकार को जैसा कि उन्होंने कहा ''संविधान के अंतकरण' की बलि नहीं चढ़ानी चाहिए। बीआर अंबेडकर की तरह ही जस्टिस मिश्र ने स्वीकार किया कि ''संवैधानिक नैतिकता' संवैधानिक सिद्धांतों की अनुपालना में ही निहित है। यह कुदरन नहीं है, बल्कि सतत प्रयासों से संवैधानिक लोकतंत्र का यह बुनियादी मूल्य सहेजा जाता है। इसी प्रकार उन्होंने ''संवैधानिक वस्तुनिष्ठता' की बात कही। कहा कि यह विचार संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी है ताकि विधायिका और कार्यपालिका अपने नियत दायरे में रह कर कार्य निष्पादन कर सकें। ऐसा इसलिए कि ''विधिक संविधानिक विास' शक्तियों के वितरण और पृथकीकरण पर आधारित है। इनमें से किसी के पास एकाधिकार नहीं है। कोई बड़ा या खुदमुख्तियार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार अनुच्छेद 239 एए (4) में ''कोईमामला' का अर्थ ''प्रत्येक मामला' नहीं होता। इस प्रकार उपराज्यपाल किसी मामले को राष्ट्रपति को प्रेषित नहीं कर सकते। उन्हें ''संवैधानिक वस्तुनिष्ठता' का ध्यान रखना होगा। इस अधिकार को दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, जिनके पीछे ठोस और वैध कारण होने चाहिए। उपराज्यपाल मंत्रिमंडल के प्रत्येक फैसले को बदलने का अधिकार नहीं रखते। भिन्न राय रखनी ही है, इसलिए मंत्रिमंडल के फैसले से भिन्न रवैया अख्तियार नहीं कर सकते। प्रधान न्यायाधीश ने स्पष्ट कहा है कि उपराज्यपाल की मंत्रिमंडल से भिन्न राय कभी भी इस अवधारणा पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि ''भिन्न राय रखने का उनके पास अधिकार' है। मत भिन्नता ''संवैधानिक विास' पर आधारित होनी चाहिए। इसी के साथ मंत्रियों को भी ध्यान रखना चाहिए कि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, और उपराज्यपाल बराय नाम मुखिया नहीं हैं, बल्कि उनके पास प्रशासक की शक्तियां हैं। दिल्ली विशेष प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है। न तो उपराज्यपाल को और न ही मंत्रियों को ऐसा सोचना चाहिए कि वे महत्त्वपूर्ण हो गएहैं, बल्कि उन्हें संवैधानिक कायदों, मूल्यों और अवधारणों के मुताबिक अपने दायित्व का निवर्हन करना है।

नागरिकता विधेयक पर असम में गुस्सा क्यों!

केंद्र सरकार नागरिकता विधेयक 1955 में जो संशोधन करना चाहती है, उसे लेकर असम में बवाल मचा हुआ है? इस विधेयक के जरिए केंद्र सरकार तीन पड़ोसी देशों के शरणार्थियों (गैर–मुस्लिम) को भारत की नागरिकता प्रदान करना चाहती है? लेकिन प्रस्तावित विधेयक ने असम में भौगोलिक विभाजन जैसा माहौल तैयार कर दिया है? ब्रह्मपुत्र घाटी के लोग इसके तीव्र विरोध में हैं तो बराक घाटी के लोग हार्दिक स्वागत में। सात 7 से 10 मई, 2018 के बीच प्रस्तावित विधेयक पर आम लोगों की राय जानने के लिए संयुक्त संसदीय समिति ने असम और मेघालय का दौरा किया था। तब से विधेयक के विरोध और समर्थन में कई बार धरना–प्रदर्शन हो चुके हैं। प्रस्तावित विधेयक में प्रावधान किया गया है कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आने वाले हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारतीय नागरिकता पाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। मौजूदा नागरिकता अधिनियम का प्रावधान है कि कोई शरणार्थी पिछले 14 सालों में से 11 सालों तक और आवेदन करने से पहले 12 महीने तक भारत मे रह रहा हो तो उसे देश की नागरिकता मिल सकती है। 19 जुलाई, 2016 को केंद्र सरकार ने संसद में संशोधन विधेयक पेश कर 3 देशों के 6 धर्मावलंबियों के लिए समय–सीमा को 14 सालों में 11 साल से घटाकर 14 सालों में 6 साल कर दिया। इससे पहले 2015 और 2016 में सरकार ने दो अधिसूचना जारी कर इन शरणार्थियों को विदेशी अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 के प्रावधानों से रियायत दे दी, जिनके तहत उनको देश से निकाला जा सकता था और 31 दिसम्बर, 2014 से पहले आए ऐसे शरणार्थियों को भारत में रहने का अधिकार दे दिया। भाजपा सांसद राजेन्द्र अग्रवाल की अगुवाई मे 16 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति ने गुवाहाटी, सिल्चर और शिलांग का दौरा किया। गुवाहाटी मे सैकड़ों संगठनों ने विधेयक के विरोध मे समिति को ज्ञापन सौंपे। एक ज्ञापन पर तो खून से भी हस्ताक्षर किए गए थे। सिल्चर में अनेक संगठनों ने विधेयक के समर्थन में ज्ञापन सौंपे। शिलांग में मेघालय मंत्रिमंडल ने विधेयक का विरोध करने का निर्णय लिया। विधेयक करने वालों का मानना है कि विधेयक पारित हो गया तो असम में घुसपैठियों की समस्या और गंभीर हो जाएगी। समर्थन करने वालों का मानना है कि इससे असम की बराक घाटी में रह रहे बंगाली हिन्दुओं के साथ न्याय हो पाएगा और अलगाव को कम किया जा सकेगा। ब्रह्मपुत्र घाटी में विधेयक का विरोध कर रहे संगठनों का कहना है कि असम में और अधिक घुसपैठियों को बसाना उचित नहीं होगा। विधेयक 1985 के असम समझौते की मूल भावना के खिलाफ है। यह समझौता तत्कालीन राजीव गांधी सरकार और अखिल असम छात्र संघ (आसू) के बीच हुआ था। समझौते में असम को बांग्लादेशियों से मुक्त करवाने की बात कही गई थी और उसमें धर्म विशेष को रियायत देने का प्रावधान नहीं किया गया था। समझौते में उल्लेख किया गया कि 24 मार्च, 1971 की आधी रात के बाद असम आए सभी घुसपैठियों को विदेशी मानकर बहिष्कृत किया जाएगा। इसके लिए नागरिकता अधिनियम मे अनुच्छेद 6 ए के तहत अलग से प्रावधान जोड़ा गया। इस संबंध में आसू के महासचिव लुरीन ज्योति गोगोई का कहना है– मतलब साफ है कि विदेशियों के लिए शेष भारत में कट ऑफ वर्ष भले ही 1950 है, लेकिन असम के लिए 24 मार्च, 1971 है। बराक घाटी और ब्रह्मपुत्र घाटी की आबादी के बीच भाषायी विभाजन की शुरुआत 1947 में ही हो गई थी, जब सिलहट के अधिकतर बंगलाभाषी अंचल पूर्वी पाकिस्तान में शामिल हो गए थे और एक अंचल भारत में रह गया था, जो बराक घाटी का अंग बना।

अन्नदाता को तोहफा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार द्वारा खरीफ फसलों के लिए न्यूतनम समर्थन मूल्यों में वृद्धि स्वागत योग्य है। भाजपा ने 2014 के आम चुनाव के अपने घोषणा पत्र में यह वायदा किया था कि सत्ता में आने पर वह फसल की लागत का डेढ़ गुणा मूल्य किसानों को देगी। यूपीए शासनकाल में गठित एमएस स्वामीनाथन आयोग ने इसकी अनुशंसा की थी, लेकिन उस दौरान इसे अमल में नहीं लाया गया। मोदी सरकार भी हर फसल के पूर्व मूल्यों में थोड़ी वृद्धि कर रही थी, लेकिन इस बार के बजट में डेढ़ गुणा मूल्य देने की घोषणा की गई। उसके अनुसार रबी की फसलों का दाम बढ़ाया गया और अब खरीफ का। हालांकि विपक्षी दल इसकी भी आलोचना कर रहे हैं, मगर उसे राजनीतिक बयान से ज्यादा महत्त्व नहीं दिया जा सकता है। कई किसान संगठनों ने भी सरकार द्वारा वृद्धि को अपर्याप्त कहा है। वस्तुतरू किसान संगठन लागत तय करने का आधार बदलना चाहते हैं। इसमें एक श्रेणी होती है सी 2। इसमें अन्य प्रत्यक्ष लागत के साथ भूमि का मूल्य, परिवार के लोगों के श्रम का पारिश्रमिक आदि शामिल करके गणना होती है। यह एक मांग है, जिस पर किसान संगठन बने रहेंगे। सरकार पर दबाव बनाए रखने की रणनीति के तहत यह रवैया स्वाभाविक है। पर मूल्य वृद्धि निराशाजनक नहीं है। अभी जो लागत मूल्य का सूत्र है, उसके अनुसार यह डेढ़ गुणा वृद्धि है। इस नाते इसका समर्थन करने में कोई हर्ज नहीं है। किसानों को थोड़ा और ज्यादा मिले इसके लिए दबाव बनाए रखा जाए। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने किसानों से मोदी एप पर बात की। उसके बाद देश भर से आए किसानों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर उनकी बातें सुनीं। उसके बाद पहले गन्ना किसानों के लिए और अब सभी किसानों के लिए यह घोषणा हुई है। किसानों की समस्या खेती की लागत में वृद्धि है। इसे कैसे कम किया जाए इस पर ज्यादा फोकस किए जाने की आवश्यकता है। अगर लागत कम हो जाए तो न्यूनतम समर्थन मूल्य में सरकार की देयता भी घट जाएगी और किसानों की परेशानियां भी कम होंगी। फसल के मूल्य बढ़ने का एक नकारात्मक असर महंगाई बढ़ने के रूप में भी आता है। खाद्यान्नों के दाम ज्यादा दिए जाएंगे तो बाजार में वह महंगा होगा ही। उसके बाद महंगाई बढ़ने का रोना आरंभ हो जाता है। यह समझना चाहिए कि किसानों को अगर उनकी पैदावार का उचित मूल्य देना है तो हमें थोड़ी महंगाई को बोझ सिर पर उठाना ही होगा।

हार के बावजूद लौटी रंगत

भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ियों के चेहरों की चमक और खुशी फिर से लौट आई है। इस चमक के लौटने की वजह हॉलैंड के ब्रेडा में हुई चौंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीतना है। यह चमक टिकने वाली रहेगी, यह आने वाले समय में पता चलेगा क्योंकि ऐसी चमक पूर्व में कई बार आती रही है पर हम इसे स्थाई रूप नहीं दे सके हैं। भारत ने अभी कुछ समय पहले एफआईएच वर्ल्ड हॉकी लीग में लगातार दूसरी बार कांस्य पदक जीता था और दो साल पहले भी चौंपियंस ट्रॉफी में रजत पदक जीता था। यह सही है कि भारत ने दो साल पहले रोलैंट ओल्टमेंस के समय में ऑस्ट्रेलिया से हारकर ही रजत पदक जीता था। लेकिन दो साल पहले वाले फाइनल और इस बार के फाइनल में परिणाम भले ही समान रहा हो पर एक भिन्नता दिखती है। दो साल पहले ऑस्ट्रेलिया टीम ने दबदबा बनाकर फाइनल जीता था। लेकिन इस बार के फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों ने ऑस्ट्रेलिया को हमलों को फिनिश देने के लिए स्पेस ही नहीं दी और दबदबा बनाए रखा। हरेंद्र सिंह के हॉकी कोच बनने का असर टीम पर साफ दिखने लगा है। लेकिन टीम की इस रंगत को बनाए रखने में हॉकी इंडिया की भी अहम भूमिका है। अभी तक वह कोच की अहमियत समझे बगैर रखती व निकालती रही है। उसने पिछले कुछ सालों में जोस ब्रासा, टैरी वाल्श, पॉल वान एस, रोलैंट ओल्टमेंस, शॉर्ड मारिने को रखने के कुछ समय बाद ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इसमें कम–से–कम दो कोच वाल्श और पॉल ऐसे थे, जो टीम में सुधार लाने की क्षमता रखते थे और उन्होंने सुधार किया भी। लेकिन अनावश्यक हस्तक्षेप से आजिज आकर वह जिम्मेदारी को बीच में ही छोड़कर चले गए। पिछली बार हॉकी इंडिया ने मारिने को पुरु ष और हरेंद्र सिंह को महिला हॉकी टीम का कोच बनाने की गलती नहीं की होती और हरेंद्र को उसी समय पुरु ष टीम की जिम्मेदारी दे दी होती तो भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में खराब प्रदर्शन का सामना नहीं करना पड़ता। भारत लगातर दो कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतने के बाद इस बार चौथा स्थान ही पा सका। इस कारण ही मारिने और हरेंद्र की अदला बदली की गई है। भारत ने ब्रेडा चौंपियंस ट्रॉफी में अपनी चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 4–0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की और फिर ओलंपिक चौंपियन ऑस्ट्रेलिया को 2–1 से हराकर अपनी क्षमता का अहसास कराया। ऑस्ट्रेलिया से 2–3 से हारने और बेल्जियम से ड्रा खेलने के बाद भारत को फाइनल में स्थान बनाने के लिए मेजबान नीदरलैंड से मैच ड्रा खेलना था। इस लक्ष्य को पाने में भारतीय टीम सफल रही और फाइनल में लगातार दूसरी बार पहुंच गई। फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारतीय टीम ने जिस तरह के खेल का प्रदर्शन किया, उससे थोड़ी राहत मिलती है। इसमें भाग्य ने जरा भारत का साथ दिया होता तो हम रजत के बजाय स्वर्ण पदक के साथ भी लौट सकते थे। तीसरे क्वार्टर में मनदीप सिंह द्वारा लगाया शॉट गोलकीपर टेलर लॉवेल को तो गच्चा देने में सफल हो गई पर गेंद बार से टकरा गई। भारत के इस प्रदर्शन में गोलकीपर पीआर श्रीजेश ने भी अहम भूमिका निभाई। फाइनल में पेनल्टी शूटआउट में गोल खाने की बात छोड़ दें तो हर मैच में उन्होंने शानदार बचाव किए। उन्हें चौंपियंस ट्रॉफी का सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना गया। पिछले कोच मारिने शॉर्ड के समय युवाओं पर जरूरत से ज्यादा जोर देकर टीम का संतुलन बिगाड़ दिया गया था। लेकिन हरेंद्र ने आते ही सरदार सिंह, बीरेंद्र लाकड़ा, सुरिंदर सिंह और रमनदीप सिंह को टीम में वापस लाकर फिर से संतुलन बनाया। इसके बाद उन्होंने पूरी टीम को एक सूत्र को पिरोने को अहमियत दी। भारत ने पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड हॉकी लीग में दो बार कांस्य पदक, चौंपियंस ट्रॉफी में दो बार रजत पदक और एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर सुधार को दिखाया है। लेकिन विश्व कप और ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन ही सबसे ज्यादा मायने रखता है और हम यहां टांय–टांय फिस्स रहे हैं। भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में आखिरी 12वां और 2016 के रियो ओलंपिक में आठवां स्थान प्राप्त किया था। वहीं 2010 के दिल्ली विश्व कप में आठवां और 2014 के हेग विश्व कप में नवां स्थान प्राप्त किया था। अगला विश्व कप इस साल घर में यानी भुवनेश्वर में होने वाला है। हरेंद्र की अगुआई में भारतीय टीम यदि विश्व कप में पोडियम पर चढ़ सकी और 2010 के टोक्यो ओलंपिक में पदक पा सकी, तब समझा जाएगा कि भारतीय हॉकी के सुधरे दिन लौट आए हैं। हरेंद्र ने थोड़े से समय में जिस तरह से टीम को एकजुट किया है, उससे लगता है कि वह इस काम का भी बखूबी कर सकते हैं पर इसके लिए जरूरी है कि हॉकी इंडिया भी कोच में भरोसा बनाए रखे।

ड्रेस कोड को लेकर सीएम योगी पर आजम का तंज

पूछा `नहीं मानी बात तो बच्चे मारे जाएंगे या मौलवी पर तेजाब डाला जाएगा ?'

लखनऊ। मदरसों में ड्रेस कोड लागू और एनसीईआरटी की किताबें पढ़ाए जाने पर प्रतिक्रियायाओं का दौर जारी है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान ने सवाल करते हुए सरकार से पूछा है कि ये भी बताया जाय कि अगर छात्र या मदरसे इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो उन्हें क्या सजा दी जाएगी?

आजम खान ने इस मुद्दे पर रे रखते हुए कहा कि सरकार को ये भी बता देना चाहिए कि नियमों को न मानने पर क्या सजा मिलेगी। नियन न मानने पर मदरसा बुलडोजर कर दिया जाएगा, बच्चे मार दिए जाएंगे या फिर टीचर्स पर तेजाब डाला जाएगा? क्या सजा दी जाएगी ये भी सरकार को बता देना चाहिए। आधी बातें समझ नहीं आती न।

उन्होंने कहा– साहब (सीएम योगी) जो दिल चाहे करें लेकिन साथ में हर जुर्म की सजा भी डिक्लेयर करते चलें। ताकि एक बार फिर यह बात बहस में आए, मिसेज इंदिरा गाँधी की इमरजेंसी क्या थी और मिस्टर नरेंद्र मोदी की इमरजेंसी क्या है। यह बात सामने आनी चाहिए। घोषित इमरजेंसी और अघोषित इमरजेंसी में वही फर्क होता है। जो सच और आधे सच में होता है। आधा सच ज्यादा खतरनाक होता है।

जो सत्य में और अर्धसत्य में होता है। अर्धसत्य असत्य से ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए घोषित इमरजेंसी से यह अघोषित ज्यादा खतरनाक है। इतना ही नहीं उन्होंने तंज कसते हुए ये भी कहा कि पहले मुख्यमंत्री योगी भी तो जीन्स पैंट पहने, फिर देखेंगे कितने अच्छे लगेगें।

मरीज के पेट से निकला स्टील का गिलास

लखनऊ। कानपुर के रामा हॉस्पिटल में पेट के ऑपरेशन का हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां

एक बुजुर्ग के पेट का ऑपरेशन कर डॉक्टरों ने स्टील का गिलास बाहर निकाला।

डॉक्टरों ने चीरा लगाकर पेट में फंसा स्टील का गिलास निकाला। दो घंटे चले आपरेशन के बाद बुधवार को मरीज की अस्पताल से छुट्टी कर दी गई। आपरेशन करने वाले रामा हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीनियर सर्जन डॉ. दिनेश कुमार ने दुर्लभ आपरेशन होने का दावा किया।

बताया कि वे इसे मेडिकल मैग्जीन में प्रकाशित होने के लिए भेजेंगे। दिबियापुर (औरैया) निवासी रामदीन (62) तिर्वा, कन्नौज मेडिकल कालेज में गार्ड है।

डॉ. दिनेश ने मरीज की ली गई हिस्ट्री का हवाला देकर बताया कि 10 दिन पहले बदमाशों ने रामदीन को पीटकर बेहोश करने के बाद लूटा और उसके गुदा द्वार में स्टील का गिलास तली की तरफ से ठूंस दिया था, जो उसके पेट में पहुंच गया था।

योगी से मिले संजय दत्त,वीके सिंह ने की भोजपुरी गायिका से मुलाकात

लखनऊ। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सम्पर्क फार समर्थन अभियान के तहत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां बालीवुड के शमुन्ना भाईय संजय दत्त और इंडिया टूडे के समूह संपादक राज छेनगप्पा का गर्मजोशी से स्वागत किया, वहीं वाराणसी में केन्द्रीय मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल वी.के. सिंह ने भोजपुरी गायिका हीरालाल यादव और उनके परिवार से मुलाकात की। केन्द्र की राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की चौथी वर्षगांठ पर श्री योगी ने बालीवुड स्टार को एक बुकलेट भेंट की। किताब में मोदी सरकार की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन है। मुख्यमंत्री ने संजय दत्त से लोकसभा चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की। वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी (सपा) ने संजय दत्त का नाम पार्टी प्रत्याशी के तौर पर रखा था, मगर ऐन वक्त पर उच्चतम न्यायालय ने उन्हें चुनाव लडने की अनुमति देने से मना कर दिया था। केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार की उपलब्धियों के बारे में जनता को जागरूक करने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मई में श्संपर्क फार समर्थन्च अभियान का श्रीगणेश किया था। संजय दत्त अपनी आगामी फिल्म प्रस्थानम की शूटिंग के सिलसिले में पिछले एक सप्ताह से लखनऊ में है। तेलुगु फिल्म की हिन्दी रीमेक में वह एक कद्दावर नेता की भूमिका में हैं। इस फिल्म के जरिये संजय जेल से रिहा होने के बाद बालीवुड में अपनी दूसरी पारी की शुरुआत कर रहे हैं। फिल्म में उनके साथ मनीषा कोइराला पत्नी की भूमिका में हैं जबकि फिल्म में जैकी श्रॉफ और चंकी पांडे भी हैं। प्रस्थानम की शूटिंग बाराबंकी, लखनऊ, कानपुर में की जा रही है। श्री योगी ने ट्विटर पर फिल्म अभिनेता के साथ अपनी फोटो अपलोड की है जिसमें मुख्यमंत्री संजय को एक किताब भेट कर रहे है। किताब पर प्रधानमंत्री के साथ उनकी फोटो है। श्री दत्त मुख्यमंत्री के आवास पर करीब आधा घंटा रुके। भेंट के दौरान फिल्म अभिनेता ने श्री योगी से उत्तर प्रदेश में फिल्म निर्माण से लेकर कई अहम मुद्दों पर काफी चर्चा भी की। उन्होने प्रदेश सरकार के

दरोगा पुत्र ने सिपाही को दौड़ाकर पीटा

लखनऊ। राजधानी में बिगड़ैल नवाबों के अंदर खाकी का भय खत्म होने लगा है। बुधवार रात आशियाना में नशे में धुत पल्सर सवार ने बाइक सवार सिपाही को टक्कर मार दी। सिपाही ने जब विरोध किया तो युवक ने फोन कर दोस्तों को बुला लिया। दरोगा पुत्र समेत तीन बिगड़ैलों ने सरेराह सिपाही को दौड़ाकर पीटा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे और तीनों आरोपितों को दबोच लिया। दरोगा पुत्र पुलिस को अर्दब में लेने लगा। पुलिस ने घायल सिपाही का मेडिकल कराकर तीनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली है।इंस्पेक्टर जितेन्द्र प्रताप सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब दस बजे थाने पर तैनात सिपाही आनन्द कुमार खाना खाने बाइक से खजाना मार्केट गया था। खजाना मार्केट के पास नशे में धुत पल्सर सवार युवक ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर लगने से सिपाही आनन्द सड़क पर गिरकर चोटिल हो गया। यह देख बाइक सवार ने फोन कर अपने दो साथियों को बुला लिया।घायल सिपाही आनन्द ने बाइक सवार युवक को नशे में बाइक चलाने की बात कहकर टोका तो वह बहस करने लगा। इसी बीच युवक के दो और साथी वहां आए और तीनों ने मिलकर सिपाही आनन्द को जमकर पीटा।

बहराइच में बुखार और डायरिया से पीड़ित दो मासूमों की मृत्यु

बहराइच। उत्तर प्रदेश में बहराइच के जिला अस्पताल में बुखार व डायरिया से पीड़ित दो मासूम रोगियों की आज इलाज के दौरान मौत हो गई। अधिकृत सूत्रों के अनुसार हुजूरपुर के लखवापुर गांव निवासी सैज खान (5) को बुखार के साथ उल्टी–दस्त की शिकायत पर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आज दोपहर में इलाज के दौरान सैज की मृत्यु हो गई। चिकित्सकों के मुताबिक वह डायरिया की चपेट में था।

बुखार और डायरिया से पीडित रामगांव के नौतला गांव निवासी धीरू (03) की भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। बुखार व डायरिया से पीड़ित 19 अन्य रोगी अस्पताल में भर्ती हुए हैं। इनमें तीन रोगियों की हालत नाजुक होने पर उन्हें गहन चिक्तिसा कक्ष में शिफ्ट किया गया है। वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. एस. दयाल ने बताया कि लगातार मौसम परिवर्तन के कारण बच्चे बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं।

रोडवेजकर्मियों ने बेच डाला 22 लाख का डीजल

लखनऊ। जब खेत ही मेढ़ खा जाएं तो किसान क्या करें। यह हाल हो गया है उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम का। आलम यह है कि रोडवेज के दो कर्मचारियों ने बसों में डीजल भरने के बजाय 36 हजार लीटर डीजल बेच दिया। जब रोडवेज मुख्यालय को इस घटना की जानकारी हुई तो अफसरों के होश उड़ गये और मुरादाबाद क्षेत्र में तैनात दो एसएसआई को निलम्बित कर दिया। साथ ही दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।प्रधान प्रबंधक कार्मिक साद सईद ने बताया कि लंबे अर्से से मुरादाबाद क्षेत्र में जब डीजल की खरीद व प्रयोग के बारे में मिलान किया गया तो पता चला कि 36 हजार लीटर डीजल का कोई हिसाब–किताब नहीं मिल रहा। इसकी जांच सहायक लेखाधिकारी एमआर खत्री के नेतृत्व में आडिट टीम ने की और अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि शैलेन्द्र बंसल ने 24 हजार लीटर व कपिलदेव ने 12 हजार लीटर डीजल का चोरी किया, जिसकी करीब 22 लाख रुपये है।

जानलेवा हमले के दो आरोपित गिरफ्तार

लखनऊ । काकोरी पुलिस ने जानलेवा हमले के मामले में नामजद दो आरोपितों को कठिंघरा पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित अजय व सूरज उर्फ सीजू काकोरी के ग्राम तेजकिशनखेड़ा के रहने वाले हैं। बताते चलें कि बीते सोमवार को मामूली बात पर हुए विवाद में दबंग अजय व सूरज ने गांव की रहने वाली रानी व उसके बेटे ओमप्रकाश पर बांके व सरिया से हमले कर दिया था। हमले में ओमप्रकाश का सिर फट गया था। पुलिस ने उक्त मामले में मां रानी की तहरीर पर मारपीट, गाली–गलौज, धमकी समेत गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की थी।

लविवि ने बनायी विस्तृत रिपोर्ट, सहमे पुलिसकर्मी

लखनऊ। लखनऊ विविद्यालय ने शुक्रवार को हाईकोर्ट के बुलावे पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली है। सूत्रों का कहना है कि लविवि के अधिकारियों ने सोमवार से लेकर बुधवार तक की सारी घटनाएं सिलसिलेवार ढंग से तैयार की है। बताया जाता है कि इन विवरण में पुलिस अधिकारियों, सीओ, एसपी ट्रांसगोमती, हसनगंज थाने को की गयी फोन काल्स और अन्य जानकारियां भी शामिल हैं। बताया जाता है कि इस मामले में अब पुलिस के आला अधिकारी बैकफुट पर हैं, लेकिन चाहकर भी लविवि इस मामले में अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है। लविवि के एक बड़े अधिकारी ने बताया कि डीजीपी द्वारा चौकी इंचार्ज को सस्पेंड करना और सीओ का ट्रांसफर करना इसी रिपोर्ट की एक कड़ी मात्र है।

मस्जिद–मदरसा किया गया सील

लखनऊ। सिद्धार्थनगर में एक मस्जिद को सील कर दिया गया। मस्जिद को बीजेपी नेता की शिकायत पर सील किया गया। जिसके बाद से इलाके मे तनाव फैला हुआ है।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मस्जिद के बाहर बड़ी संख्या मे पुलिस की भी तैनाती भी की हुई है। मस्जिद सीज करने की कार्यवाही प्रभारी मंत्री चेतन चौहान की अध्यक्षता में हुई। आरोप है कि मस्जिद का निर्माण नगर पालिका से आवासीय भवन का नक्शा पास कराकर किया गया।

भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्यामधनी राही की और से की गई शिकायत मे कहा गया कि आवासीय भवन के नक्शे पर दो मंजिली मस्जिद व मदरसे का निर्माण कराकर 17 मई को लाउडस्पीकर से ऐलान किया गया कि यह मस्जिद और मदरसा है। ऐसे मे बीजेपी विधायक की शिकायत पर एसडीएम सदर की ओर से निर्माणाधीन भवन (जिसे

मस्जिद मदरसा कहा जा रहा है) को कुर्क करते हुए उसे सील कर दिया।

एसडीएम राजेश सिंह ने बताया कि हसमुल्ला पुत्र रोशई की ओर से दिये गए आवेदन पर नियत प्राधिकारी विनियमित क्षेत्र नौगढ़ की ओर से 13 नवंबर 2017 को उक्त जमीन पर आवासीय भवन निर्माण का नक्शा पास कराया गया।

फिर नियम विरुद्ध तरीके से इस पर मदरसा व मस्जिद का निर्माण करा दिया गया।

उन्होने कहा कि बिना इजाजत कहीं भी मदरसा व मस्जिद का निर्माण कराया जाना अवैध है। इसी के तहत कार्यवाही करते हुए भूमी को कुर्क कर निर्माणाधीन भवन को सील कर दिया गया। अब इस मामले में तीनों विपक्षीगणों को सुनवाई के लिये 18 जून को उपस्थित होने की नोटिस दी गयी है।

चार साल पहले बर्खास्त 15 ट्रेनी जज हुए बहाल

कोर्ट ने कहा कि इन ट्रेनी जजों का कोर्ट में आचरण पर प्रश्न नहीं था

लखनऊ । इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने लगभग चार साल पहले लखनऊ के फैजाबाद रोड स्थित चरन क्लब एंड रिसार्ट में शराब पीकर आपस में लड़ने के कारण सेवा से हटाये गए पंद्रह ट्रेनी सिविल जजों को बहाल करने का आदेश दिया है । कोर्ट ने उन्हें हटाने संबंधी 14 सितंबर, 2014, 22 सितंबर, 2014 और 15 जून, 2015 को पारित तीन आदेशों को खारिज कर दिया । ये आदेश हाईकोर्ट की पूर्णपीठ ने प्रशासनिक कार्य करते हुए पारित किये थे । कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट प्रशासन तत्काल इन हटाये गए ट्रेनी जजों को सेवा में वापस ले ।

यह आदेश जस्टिस सत्येंद्र सिंह चौहान व जस्टिस रजनीश कुमार की बेंच ने हटाये गए ट्रेनी जजों की अलग–अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी करते हुए पारित किया । कोर्ट ने कहा कि इन ट्रेनी जजों का कोर्ट में आचरण पर प्रश्न नहीं था और न ही उनके न्यायिक कामकाज

के तरीके पर । उन्होंने अपनी ट्रेनिंग भी सफलता पूर्वक पूरी कर ली थी, लेकिन ट्रेनिंग के अंतिम दिन उनसे जो हरकत हुई उसकी वजह से उन्हें सेवा से बिना सुनवायी का पूरा मौका दिये हटाना उचित नहीं था ।

बेंच ने कहा कि ये ट्रेनी जज युवा थे और उन्हें इस बात का अनुभव नहीं था कि कोर्ट के अंदर व बाहर किस प्रकार का व्यवहार न्यायिक अधिकारियों से अपेक्षित होता है । ट्रेनी जज आपस में ही झगड़े थे और उन्होंने वहां मौजूद किसी महिला से दुर्व्यवहार नहीं किया था। दूसरे दिन घटना के लिए एक दूसरे से माफी भी मांग ली थी । ऐसे में उन्हें सुधरने का मौका देने की बजाय सीधे सेवा से हटा देना उचित नहीं था । गौरतलब है कि याची ट्रेनी जजों ने 2013 में पीसीएसजे की परीक्षा पास की थी और विभिन्न जिलों में बतौर सिविल जज व जूनियर जज नियुक्त हुए थे । जेटीआरआई में ट्रेनिंग के लिए उन्हें बुलाया गया था । सात सितंबर, 2014 को ट्रेनिंग खत्म होने की पूर्व संध्या पर सभी 15 ट्रेनी जज चरण क्लब और रिसार्ट में पार्टी करने पहुंचे थे।

कान के मरीजों का इलाज हुआ आसान

लखनऊ। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर अस्पताल में अब कान की सर्जरी कराना बेहद ही आसान हो गया है। अस्पताल के डायरेक्टर राजीव लोचन ने इलेक्ट्रॉनिक कैमरा मशीन मरीजों के हित और डॉक्टरों की सफलता को लेकर एक पहल किया है।

इस मशीन से स्क्रीन में साफ कान की संकरी नली के अंदर देखा जा सकता है। इससे पहले बेहतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं होने के कारण डॉक्टरों को ऑपरेशन करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।

अब बलरामपुर अस्पताल में इलेक्ट्रॉनिक कैमरा मशीन लगाई गई है। यह मशीन आने वाले दिनों में मरीजों के लिए लाभकारी होगी।

वहीं बलरामपुर अस्पताल के डायरेक्टर राजीव लोचन ने बताया कि इस मशीन से मरीजों की कान की सर्जरी आसानी से की जा सकती है।

एक लाख ओबीसी युवाओं को दिया जाएगा रोजगार : मंत्री ओमप्रकाश राजभर

लखनऊ। पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने कहा है कि वर्ष 2022 तक कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना के माध्यम से एक लाख ओबीसी युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।

साथ ही विभाग की ओर से पिछड़े वर्ग के युवाओं के लिए आईएएस–पीसीएस समेत सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी की जाएगी।

वे शुक्रवार को योजना भवन में ऑनलाइन 'ओ लेवल' और 'ट्रिपल सी' कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है।

इस ऑनलाइन योजना का संचालन डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत हो रहा है। राजभर ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में पिछड़े वर्ग के 7500 छात्र–छात्राओं को ओ लेवल और 10500 से अधिक छात्र–छात्राओं को ट्रिपल सी का प्रशिक्षण दिलाने का लक्ष्य है।

भाजपा नेता की ज्वैलरी शॉप में लाखों की चोरी

दुकान के पीछे से नकब लगाकर घुसे थे चोर

नाराज दुकानदारों व ग्रामीणों ने किया हंगामा डॉग स्क्वॉयड व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने की पड़तालबंथरा स्थित हरौनी चौकी के पास हुई वारदात

सरोजनीनगर–लखनऊ। बंथरा स्थित हरौनी चौकी से चंद कदमों की दूरी पर चोरों ने बुधवार देर रात भाजपा नेता की ज्वैलरी शॉप में नकब लगाकर लाखों के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। गुरुवार सुबह छोटा भाई दुकान खोलने पहुंचे तो घटना की जानकारी हुई। चौकी के पास हुई वारदात की सूचना के बाद भी पुलिस कई घण्टों तक नहीं पहुंची। इससे आक्रोशित दुकानदारों व ग्रामीणों ने हंगामा शुरू कर दिया। पुलिस ने जल्द खुलासे का आश्वासन देकर शांत कराया। पुलिस ने डॉग स्क्वॉयड व फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट की मदद से पड़ताल की है।ककौंहा गांव निवासी भाजपा नेता वीरेन्द्र रावत की बनी–मोहान रोड स्थित हरौनी कस्बे में वीरेन्द्र ज्वैलर्स के नाम से आभूषण की दुकान है। दुकान पर वीरेन्द्र और उसका छोटा भाई सुरेन्द्र बैठता है। रोजाना की तरह बुधवार शाम भी दोनों भाई दुकान बंद कर घर चले गए। गुरुवार सुबह छोटे भाई सुरेन्द्र ने जब दुकान खोली तो उसके होश उड़ गए। उसे दुकान के पिछले

हिस्से की दीवार कटी होने के साथ ही अन्दर रखा सारा सामान अस्त व्यस्त मिला। सुरेन्द्र ने इसकी जानकारी बड़े भाई वीरेन्द्र व पुलिस को भी दी। सूचना के काफी देर बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। जिससे नाराज दुकानदारों ने वहीं पर हंगामा शुरू कर दिया। हंगामे की जानकारी पाकर पहुंची पुलिस ने जल्द ही घटना का खुलासा करने का आश्वासन देकर उन्हें शांत किया। पुलिस ने फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट व डॉग स्क्वॉयड को बुलाया। फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट ने घटनास्थल से कुछ नमूने हासिल किये हैं। वहीं, खोजी कुत्ता दुकान से करीब पांच सौ मीटर दूर हरौनी गांव तक जाने के बाद वापस लौट आया। दुकान मालिक वीरेन्द्र का कहना है कि दुकान में करीब साढ़े पांच लाख के गहने व 12 हजार की नकदी रखी थी, जो गायब है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

अलीगंज में टायर गोदाम में आग से लाखों की क्षति

लखनऊ। अलीगंज में एक बहुमंजिली इमारत के बेसमेंट में स्थित टायर गोदाम में गुरुवार प्रातरू आग लगने से अफरा–तफरी मच गयी। सूचना पर हजरतगंज व इन्दिरानगर से चार दमकल मौके पर पहुंची और दमकलकर्मियों ने दो घंटे की कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग के धुएं व पानी से काम्प्लेक्स के कई दुकानदारों को भी आर्थिक क्षति पहुंची। अलीगंज थाना क्षेत्र में रैदास मन्दिर रेलवे क्रासिंग के पास स्थित एक काम्प्लेक्स में दर्जनों दुकानें हैं। इसके बेसमेंट में शॉप नम्बर–4 में पप्पू साइकिल स्टोर का गोदाम था जहां साइकिल व मोटरसाइकिल के टायर–ट्यूब बड़ी संख्या में रखे गये थे। गुरुवार प्रातरू करीब 6.45 बजे गोदाम से धुआं निकलने लगा, किसी राहगीर ने पुलिस व दमकल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे इन्दिरानगर फायर स्टेशन से दो दमकल के कर्मचारियों ने शटर तोड़कर धुआं बाहर निकाला और आग बुझाने का प्रयास किया। आग बढ़ती देख फायर अफसर उमाकान्त ने हजरतगंज फायर स्टेशन से मदद मांगी तो दो और दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची तब करीब दो घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका।

योगी सरकार की नई पहल, 68 जिलों में खुलेंगे गो–संरक्षण केंद्र

लखनऊ। राज्य सरकार ने प्रदेश में निराश्रित–बेसहारा गोवंश की समस्या के निराकरण के लिए 68 जनपदों में एक–एक वृहद गो–संरक्षण केंद्र की स्थापना किए जाने के लिए मानकों का निर्धारण कर दिया है और इसके लिए 34 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं।

शासन ने प्रत्येक वृहद गो–संरक्षण केंद्र के लिए 120 लाख प्रति जनपद की दर से कुल 8160 लाख रुपये का प्राविधान वर्तमान वित्तीय वर्ष में किया है, जिसके सापेक्ष प्रथम किश्त के रुप में 50.00 लाख रुपये प्रति जनपद की दर से कुल 34 करोड़ रुपये स्वीकृत करते हुए तत्काल 68 जनपदों के जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रमुख सचिव पशुधन डॉ. सुधीर एम बोबड़े की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि निर्धारित न्यूनतम मानक

के अनुसार अथवा उससे बड़े मानक के वृहद गो–संरक्षण केंद्रों की स्थापना जनपदों में की जाएगी। सरकार ने 68 जनपदों में बनाये जाने वाले गो–संरक्षण केदों के मानक निर्धारित कर दिए हैं, जिसके तहत प्रत्येक केंद्र में अलग–अलग 4 गोवंश शेड जिनका कुल क्षेत्रफल 14,000 वर्ग फीट हो, 02 भूसा गोदाम, जिनका कुल क्षेत्रफल 2,000 वर्गफीट होना चाहिए।

कार्यालय, औषधि कक्ष, स्टोर–300 वर्गफीट तथा 06 कर्मचारी आवास एवं शौचालय, स्नानागार, जिनका कुल क्षेत्रफल–1,100 वर्गफीट होगा। चारा पानी के लिए 4 चरहियां, जिनका कुल क्षेत्रफल–800 वर्गफीट एवं शेडो के बाहर भी खुले में कुछ चरनियां, जिनका कुल क्षेत्रफल 5,400 वर्गफीट हो तथा जिन पर बाद में यथावश्यकता शेड बनाया जा सके। इसके अलावा पम्प हाउस का निर्माण, जिसमें उपर्युक्त क्षमता का सबमर्सिबल पम्प–सोलर वाटर पम्प स्थापित किया जाए तथा दस हजार क्षमता की पानी टंकिया स्थापित की जाए। साथ ही बाउंड्रीवाल व शेडों के पृथकीकरण के लिए बाड़ की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए।

यूपी में बनेंगे फाइटर प्लेन पैदा होंगी 2.5 लाख नौकरियां

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने रक्षा क्षेत्र की ओर निवेशकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बड़ा कदम उठाया है। जिसके तहत मंगलवार को कैबिनेट ने यूपी रक्षा और एयरोस्पेस इकाई एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2018 को मंजूरी दे दी है। इससे अब प्रदेश में फाइटर प्लेन, टैंक, हेलीकॉप्टर समेत सभी तरह के रक्षा उपकरण बनाए जा सकेंगे।

सरकार ने बयान जारी कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में डिफेंस कॉरिडोर बनाने की दिशा में सरकार के वादे को लेकर ये एक और अहम कदम है। डिफेंस कोरिडोर के लिए बुंदेलखंड में 3000 हेक्टेयर जमीन की पहचान यूपी एक्सप्रेसवे इन्डस्ट्रियल डेवेलेपमेंट ऑथोरिटी ने कर ली है। इसके अधिग्रहण की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। सरकार के मुताबिक, डिफेंस कॉरिडोर निवेशकों को आकर्षित करेगा और इसके जरिए सूबे में 50 हजार करोड़ रुपए का संभावित निवेश

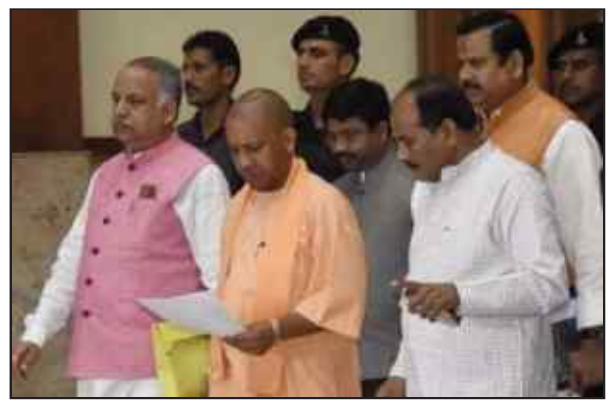

होगा।

डिफेंस कोरिडोर के निर्माण के बाद यूपी में फाइटर प्लेन, टैंक और हेलीकॉप्टरों का निर्माण होगा। मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय ने बताया है कि कई निजी और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कोरिडोर में निवेश के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने कहा कि नीति के अमल में आने के बाद उप्र में रक्षा क्षेत्र में कई बड़ी कंपनियां निवेश करेंगी।

इन 6 जिलों से गुजरेगा एक्सप्रेसवे, पैदा होंगी 2.5 लाख नौकरियां

सूबे सरकार के मुताबिक, इस प्रोजेक्ट के कार्यरत होने पर न सिर्फ यूपी की ओर निवेशकों का ध्यान आकर्षित होगा, बल्कि इससे आने वाले पांच साल के भीतर 2.5 लाख नौकरियां भी पैदा होंगी। एक्सप्रेसवे प्रदेश के छह जिलों, अलीगढ़, आगरा, कानपुर, लखनऊ, झांसी और चित्रकूट से गुजरेगा।

डिफेंस कॉरिडोर के लिए आधारभूत ढांचा विकसित करने की जिम्मेदारी उप्र एक्सप्रेस–वे विकास प्राधिकरण संभालेगा। कोरिडोर को मेगा ऐंकर यूनिट और ऐंकर यूनिट के तहत बनाया जाएगा। जिसमें एक हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश मेगा एंकर की श्रेणी में और एक हजार करोड़ रुपए से कम निवेश वाली कंपनियां ऐंकर यूनिट के तहत आएंगी।

प्रमुख सचिव (सूचना) अवनीश अवस्थी ने बताया है कि कैबिनेट ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 12,000 करोड़ रुपए का बैंक लोन लेने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए पंजाब नेशनल बैंक को लीड बैंक बनाया गया है।

पुरानी रंजिश में की गयी थी वृद्धा की हत्या

लखनऊ। गुलजारनगर में बुजुर्ग दुरपती (60) की हत्या के मामले में बाजारखाला पुलिस ने बुधवार देर रात ही नामजद तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने तीनों को नवनिर्मित ऐशबाग रेलवे स्टेशन के पिछले गेट के पास मल गोदाम रोड से पकड़ा। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त डण्डा बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपित महिला के पास उसका दुधमुंहा बच्चा भी है।गिरफ्तार आरोपितों में सुनील उर्फ बब्लू, राजकुमारी व मोहिनी जायसवाल निवासी मछली मण्डी गुलजारनगर बाजारखाला बताया। पुलिस फरार दो आरोपितों राजकुमार व उसके बेटे दीपक की तलाश में छापेमारी कर रही है। सीओ बाजारखाला ने बताया कि करीब बीस साल पहले दुरपती ने छेड़छाड़ की रिपोर्ट दर्ज करायी थी। उक्त मामले में राजकुमार के परिवार को आरोपित बनाया गया था।इसी बात की उनके बीच रंजिश चल रही थी। बुधवार देर रात बांस के डण्डे जमीन में गाड़े जाने पर दुरपती ने राजकुमारी व मोहिनी को भला–बुरा बोल दिया था। इस पर राजकुमार व अन्य ने दुरपती पर लाठी–डण्डे से हमला कर दिया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी लोग भाग निकले थे।

पुलिस ने घायल दुरपती को बलरामपुर अस्पताल पहुंचाया था, जहां उसने दम तोड़ दिया था। पुलिस ने देर रात ही उक्त मामले में बलवा, गैर इरादतन हत्या समेत गंभीर धाराओं में सुनील, राजकुमार, दीपक, मोहिनी व राजकुमारी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। इंस्पेक्टर बाजारखाला सुजीत कुमार दुबे ने बताया कि फरार आरोपित राजकुमार व दीपक की तलाश की जा रही है। नामजद आरोपित में मोहिनी के दुधमुंहा बच्चा भी है। मां के साथ पुलिस ने उसे भी जेल भेजा है। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिवारवालों के सुपुर्द कर दिया गया है।

कैप्टन मनोज पांडेय के शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन

कैप्टन मनोज पांडेय की जन्मभूमि रूठा में सँमर्द्धि फाउंडेसन द्वारा उनके शहीद दिवस के अवसर पर सँमर्द्धि फाउंडेसन के द्वारा कार्यक्रम किया।

इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में धर्मेंद्र सिंह ने कैप्टन मनोज पांडेय की प्रतिमा पर मालार्पण किया कैप्टन मनोज पांडेय के चाचा कौशल किशोर पांडेय का नन्ही समाज सेविका आयुषी तिवारी द्वारा माला पहनाकर सम्मान किया गया

और संस्था की चेयरपर्सन द्वारा अंगवस्त्र और फल दिए गए बच्चो को स्कूल जाने के लिए प्रेरित करते हुए बच्चों को स्कूल बैग दिए गए और इस अवसर पर कैप्टन मनोज पाण्डेय के पार्क में संस्था द्वारा बृक्षारोपण भी किया गया

इस अवसर पर ग्राम प्रधान राधेश्याम मिश्रा ,सत्य प्रकाश सिंह इस अवशर पर संस्था के सचिव आयुष तिवारी ने कैप्टन मनोज के जीवनकाल पर प्रकाश डालते हुए बच्चों से उनके जीवन से सीखें मनोज पांडेय ने न सिर्फ कमलापुर का ही नही वरन

पूरे देश मे कमलापुर का नाम रोशन कर दिया आजके युवाओ के लिए प्रेरणा लेनी चाहिये

इस अवसर पर शुशील सिंह ,रहीश, के के मिश्रा, महेंद्र मिश्रा, पुनीत मिश्रा तेजस्व बाजपेई आदि प्रमुख नागरिक मौजूद थे।

शादी का झांसा देकर युवती से दो साल तक किया दुष्कर्म

लखनऊ। मलिहाबाद इलाके में शादी का झांसा देकर आरोपित दो साल तक युवती से दुष्कर्म करता रहा। कुछ दिन पहले पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपित ने इंकार कर दिया। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर लिया है।थाना क्षेत्र में 18 साल की युवती परिवार संग रहती है। पीड़िता ने बताया कि गांव में रहने वाले अमित कुमार से

उसकी दोस्ती थी। करीब दो साल पहले अमित ने शादी का झांसा देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता का कहना है कि अमित कहता था कि अभी तुम नाबालिग हो, बालिग होने पर शादी कर लूंगा। करीब दो साल तक अमित उसका यौन शोषण करता रहा।हाल ही में पीड़िता बालिग हो गयी। बीते मंगलवार को पीड़िता की अमित से मुलाकात हुई। उसने शादी की बात कही तो अमित ने शादी से इंकार कर दिया। पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपित ने उसे जान से मारने की धमकी दी। पीड़िता ने आपबीती घरवालों को बतायी। उसके बाद वह मलिहाबाद कोतवाली पहुंची। पीड़िता ने आपबीती बताते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दुष्कर्म व जान से मारने की धमकी की रिपोर्ट दर्ज पड़ताल शुरू की। पुलिस ने बुधवार को आरोपित अमित कुमार को गिरफ्तार कर लिया है।

तहसील प्रांगण में उव,प्रव लेखपाल संघ ने काली पट्टी बांध कलम बंद हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया

बिसवां–तहसील प्रांगण में उ0 प्र0 लेखपाल संघ की प्रांतीय कार्यकारिणी के आवाहन पर तहसील अध्यक्ष सौरभ यादव के नेतृत्व में सैकड़ो लेखपालों ने काली पट्टी बांधकर कलमबंद हड़ताल करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और 8 सूत्रीय ज्ञापन उपजिलाधिकारी शशि भूषण राय को सौंपा।

ज्ञापन में मांग कि गयी है कि वेतन उच्चीकरण प्रारम्भिक ग्रेड पे 2800 किया जाये, वेतन विसंगति दूर की जाये, 2001 में चयनित 2003 2004 में प्रशिक्षित तथा 2005 में नियुक्त लेखपालों को पुरानी पेंशन दिया जाये, वेतन भत्ता दो हजार,मोटर साईकिल भत्ता पन्द्रह सौ तथा , स्टेशनरी भत्ता साढे सात सौ रूपए किया जाये, लेखपालों को लैपटाप व् स्मार्ट फोन दिए जाये,

लेखपालों के प्रोन्नति के अवसर बढ़ाये तथा राजस्व निरीक्षक के संग्रह अमीन तथा

भूमि अध्यापित आमीन का कोटा समाप्त किया जाये तथा समय पर डी सी पी कराया जाये इत्यादि प्रमुख मांगे है अध्यक्ष सौरभ यादव ने बताया कि समस्त लेखपाल 8 जुलाई तक कलमबंद हड़ताल पर रहेंगे तथा 9 जुलाई से जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना होगा।

प्रदर्शन के दौरान संरक्षक रहमतुल्लाह, मंत्री नीलेश यादव अनुपम बाजपई, रामकुमार यादव , विनीत सिंह, बजरंग रावत सतेंद्र यादव सुरेश सिंह ,मनीष दिनेश सिंह नीतू पूनम दीप्ती मिश्रा अमर सिंहइत्यादि लेखपाल मौजूद रहे

मादक पदार्थों की तस्करी में दो कैरियर गिरफ्तार

लखनऊ। बंथरा पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी में दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के पास से साढ़े सात किलो गांजा व नकदी बरामद की है।इंस्पेक्टर विद्यासागर पाल ने बताया कि उपनिरीक्षक विनोद कुमार टीम के साथ बुधवार को गश्त पर थे। सूचना मिली कि आजाद विहार मोड़ पर दो युवक मादक पदार्थ के साथ मौजूद हैं। इस पर पुलिस ने दोनों युवकों को दबोचा। पुलिस ने बैग की तलाशी ली तो एक में पांच किलो छह सौ ग्राम गांजा व दूसरे बैग में एक किलो नौ सौ ग्राम गांजा बरामद हुआ। पूछताछ में दोनों ने अपना नाम गोपाल निवासी भागलपुर बिहार व मोहन निवासी ईटगांव थानगांव सीतापुर बताया। पड़ताल में सामने आया कि आरोपित गोपाल आशियाना व मोहन कृष्णानगर में किराए पर रहते हैं। बरामद माल की कीमत करीब एक लाख रुपये बतायी जा रही है।

मवेशी चराने गये अधेड़ को सांड़ ने मार डाला

मोहनलालगंज–लखनऊ। मोहनलालगंज के गौरा गांव में गुरुवार शाम आवारा सांड़ ने मवेशी चराने गये किसान पटक–पटक कर मार डाला। लाठी–डन्डे लेकर चरवाहा दौड़े तब जाकर सांड़ मौके से भागा। उसके बाद गामीणों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

वन विभाग के अधिकारियों से आवारा सांड़ों को पकड़े जाने की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। ग्रामीणो ने इस घटना के लिए आक्रोश व्याप्त किया है।गौरा के मजरा पल्टिहा निवासी दुग्रेश ने बताया उसके पिता रामसेवक (55) गुरुवार शाम को खेत में जानवर चराने गये थे। शाम पांच बजे के करीव वह जंगबहादुर की बाग में बैठे थे, तभी उनपर एक आवारा सांड़ ने अचानक हमला कर दिया। सांड़ ने सींग उन्हें पेट में घोंपकर पटक दिया जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी। चीख–पुकार सुनकर खेतो में मौजूद जानवर चराने वाले अन्य गांव वाले लाठी–डन्डे लेकर दौड़े तब जाकर सांड़ मौके से भागा। परिजनों से सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रामसेवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के परिवार में पत्नी व तीन बेटियां सोनी, अनिला, बेटा मठोला व बेटा दुर्गेश हैं।

डीएम के निर्देश के बावजूद जिला पंचायत की लापरवाही, नहीं चालू किये कांजी हाउस

मोहनलालगंज–लखनऊ । मोहनलालगंज तहसील के दर्जनों गांवों में शहर से लाकर छोड़े गये आवारा सांड़ों के साथ अन्य जानवरों द्वारा फसल नष्ट किए जाने से परेशान किसानों ने भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के पदाधिकारी व किसानों के साथ मोहनलालगंज में तहसील दिवस पर जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा से लिखित शिकायत कर क्षेत्र के बंद पड़े कांजी हाउस चलाये जाने की मांग की थी। जिलाधिकारी ने मामले को गम्भीरता से लेते हुए जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को निर्देशित करते हुए किसानों को आवारा पशुओं से निजात दिलाये जाने के लिए कांजी हाउस चलाये जाने व 15 दिनों में कार्रवाई से अवगत कराने के निर्देश दिए थे लेकिन नौ महीने बीत जाने के बाद भी कांजी हाउस नहीं चालू हुए। मोहनलालगंज कांजी हाउस में तो जिला पंचायत के अधिकारियों की मिलीभगत से वर्षो से दुकानें संचालित हैं। आवारा सांड़ों ने1 नवम्बर2017 को मरूई गांव के बुजुर्ग नन्हकऊ यादव की जान ले ली थी।

डहलर के मुकाबले मोदी की उम्र पार कर गया रुपया : प्रमोद तिवारी

लखनऊ। बढ़ती महंगाई, रुपये की गिरती कीमत और काले धन को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर कटाक्ष किया और कहा कि वादा किया गया था कि भाजपा के सत्ता में आने पर 1 अमेरिकी डॉलर 30–35 रुपये के बराबर हो जाएगा। मोदी का यह वादा भी जुमला ही निकला और डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मोदी की उम्र को भी पार कर गया।

फिल्म सोन चिरैया को लेकर है बेहद एक्साइटेड है भूमि पेडनेकर

बॉलीवुड में दम लगा के हइशा और टॉयलेट एक प्रेम कथा जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुकी भूमि पेडनेकर इन दिनों अभिषेक चौबे के निर्देशन में बन रही फिल्म सोन चिरैया में काम कर रही है। सोन चिरैया में भूमि पेडनेकर के अलावा सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी भी मुख्य किरदार में नजर आएंगे। फिल्म की कहानी पर नजर डाले तो यह फिल्म चंबल के डकैतों पर आधारित है।

आपको बता दे की बॉलीवुड अभिनेत्री भूमि पेडनेकर अपनी इस आने वाली फिल्म सोन चिरैया को लेकर बेहद उत्साहित है। भूमि अपने आने वाली फिल्म 'सोन चिरैया' को लेकर उत्साहित हैं। भूमि ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर फिल्म का पहला लुक साझा किया। तस्वीर में सुशांत सिंह राजपूत और मनोज वाजपेयी डकैतों के लुक में नजर आ रहे हैं।

भूमि ने तस्वीर के कैप्शन में लिखा, हमें आठ फरवरी को रिलीज हो रही सोन चिरैया में देखें। बहुत गौरवान्वित और उत्साहित हूं। रॉनी स्क्रूवाला, अभिषेक चौबे, सुशांत सिंह राजपूत, मनोज वाजपेयी, रणवीर शौरी। बता दें कि फिल्म का दूसरा पोस्टर सामने आ चुका हैं। इस पोस्टर में पहली बार फिल्म की पूरी स्टारकास्ट नजर आ रही हैं।

रिलीज हुए पहले पोस्टर में सभी स्टार डकैट के रुप में नजर आ रहे हैं। पोस्टर के साथ टैगलाइन दी गई है बैरी बेईमान, बागी सावधान। बता दें कि इस पोस्टर से पहले फिल्म से भूमि और सुशांत का लुक रिलीज किया गया था जिसने इंटरनेट पर सनसनी मचा दी थी। फिल्म के रिलीज हुए इस पोस्टर में फिल्म की स्टारकास्ट पहली बार साथ नजर आ रही हैं। सोनचिरैया 08 फरवरी 2019 को प्रदर्शित होगी।

सपा समर्थक महिलाओं पर बरसीं लाठियां

लखनऊ। महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार, बिगड़ी कानून व्यवस्था और पेट्रोल–डीजल के दामों में बढ़ोतरी समेत तमाम मुद्दों को लेकर मंगलवार को हजरतगंज में विरोध प्रदर्शन कर रही समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई महिलाओं को चोट आई।

पुलिस के लाठीचार्ज में सिर में चोट लगने से सपा एमएलसी लीलावती कुशवाहा की गंभीर रूप से हालत हो गई, उन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

सपा कार्यकत्रियों पर लाठीचार्ज उस वक्त किया गया, जब वे राजभवन घेरने जा रही थीं। समझाने की कोशिश में सपा कार्यकत्रियों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई। फिर पुलिस ने आव देखा ना ताव और महिलाओं पर लाठियां बरसा दीं। महिलाओं का आरोप है कि पुरुष पुलिसकर्मियों ने महिला कार्यकर्ताओं पर लाठी बरसाई।

प्रदेश की कानून व्यवस्था, महंगाई, महिलाओं पर अत्याचार और पेट्रोल–डीजल–एलपीजी के दामों में बढ़ोतरी समेत कई मुद्दों को लेकर आज सपा की महिला सभा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया।

(पृ. 1 का शेष) . . . **छात्रों के भारी विरोध**. . . प्रवेश नहीं मिलेगा ऐसा कहीं भी नियम में नहीं लिखा है। प्रदर्शन में विनय यादव, अंकित सिंह बाबू, महेंद्र सिंह समेत अन्य छात्र शामिल रहे।

2 जुलाई से लखनऊ विश्वविद्यालय में पूजा शुक्ला समेत कई छात्र अपने एडमिशन के लिए भूख हड़ताल पर बैठे हैं. जिन की न तो सुनवाई वीवी कर रहा है और ना ही कोई प्रशासनिक अमला. कोई भी छात्रों से मिलने तक नहीं आया.

जिसके बाद आज समाजवादी प्रवक्ता जूही सिंह एलयू परिसर में पहुंची और छात्रों के अनशन में हिस्सा बनी है. उसके बाद छात्र और उग्र हो गये और वीसी एसपी सिंह की गाड़ी के सामने आ कर विरोध प्रदर्शन करने लगे.

इस चौरान उनकी पुलिस से धक्कामुक्की हो गयी. मामला इतना गंभीर हो गया की हाथापाई तक शुरू हो गयी. छात्रों ने शिक्षकों से भी मारपीट की.

इन सब के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया है.

लेखपालों की हड़ताल पर 6 माह के लिए लगाया प्रतिबंध

लखनऊ। लैपटॉप, वेतन भत्ता सहित आधा दर्जन मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रहे लेखपालों ने अब आर–पार की लड़ाई का आह्वाहन किया था। प्रदेश के सभी तहसीलों के लेखपाल मंगलवार से कलमबंद हड़ताल करने वाले थे। इसके बाद भी उनकी मांग नहीं पूरी हुई तो वें 9 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इसी बीच लेखपालों की हड़ताल पर 6 माह के लिए प्रतिबंध लगा दिया। प्रमुख सचिव राजस्व ने आदेश जारी किए हैं। हड़ताल करने वालों पर एस्मा लगेगा। लेखपाल संघ लंबे समय से मांग कर रहा है उन्हें लैपटॉप दिया जाए ताकि वे समस्याओं का समाधान कर सके। लेखपालों का दावा है कि लैपटाप न होने के कारण उन्हें आनलाइन रिपोर्ट लगाने में काफी दिक्कत होती है।

पशुओं की चर्बी गलाकर घी बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार

लखनऊ। पशुओं की चर्बी गलाकर नकली घी बनाकर बाजार में बेचने वाले गिरोह के एक सदस्य को नकली माल के साथ पुलिस ने दबोचा है। वहीं, तीन अपराधी मौके से फरार हो गये। पकड़े गए अभियुक्त के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी सुजीत कुमार राय ने बताया कि मंगलवार को मुखबिर से सूचना मिली कि कुछ युवक नकली घी डीसीएम में लादकर बाजार में बेचने जा रहे हैं। इलाके में घेराबंदी कर पुलिस ने डीसीएम सहित एक युवक को पकड़ लिया, जबकि तीन युवक मौके से फरार हो गये। पकड़े गए युवक बाजारखाला के हबीबनगर निवासी मोहम्मद सलीम ने कबूला कि हम पालतू पशुओं की हत्या कर उनकी चर्बी से गलाकर घी बनाते हैं। इसके बाद उसे कनस्तर में भरकर भाई जाबिर, फारुख और राशिद सभी मोतीझील निवासी की मदद लेकर बाजार में दुकानदारों को बेचते हैं। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पशुओं की चर्बी से तैयार किया गया 50 पीपा घी डीसीएम के साथ पकड़ा है। पकड़े गए अभियुक्त को जेल भेजते हुए फरार अन्य लोगों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं।

देवीगंज में विद्यालय के बगल में संचालित हो रहा है वीयर व देसी शराब का ठेका

रामसनेहीघाट बाराबंकी सरकार के लाख प्रयासों के बावजूद बाराबंकी के आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी की उदासीनता की वजह से क्षेत्र में सरेआम आबकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है।

तहसील रामसनेहीघाट क्षेत्र में स्थित वीयर व अंग्रेजी शराब के दुकानों में खुलेआम आबकारी नियमों की धज्जियाँ उड़ाई जाती है आलम ये है पूरे दिन इन ठेकों पर ही शराब और बीयर पीने के सारे साजो सामान उपलब्ध रहते हैं इन ठेकेदारों को पुलिस व प्रशासन का जरा भी खौफ नही है व आबकारी द्वारा निर्धारित मूल्य से कहीं ज्यादा देवीगंज चौराहा सहित आदि स्थानों पर बीयर की बिक्री की जाती है जिससे आये दिन ग्राहक और दुकान वालों से झड़प होना आम बात है कुछ स्थानों पर ठेकों का संचालन स्कूल और मंदिर के बगल ही होता है जिसका जिगता जगता उदाहरण देबीगंज चौराहे पर स्थित बीयर और देसी शराब का ठेका है इन दोनो दुकानों के बीच में ही डॉ. ब्रम्हा बक्श गोपाल पब्लिक स्कूल पिछले कई वर्षों से संचालित हो रहा है

इन दुकानों पर शराबियों के जामवाड़ों से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों पर गलत प्रभाव पड़ता है किँतु जिम्मेदार अधिकारी और क्षेत्रीय प्रशासन आँखे मूदें हुए हैं।

अवध की बेटी बनी अनाथों की आवाज

वीकेस्ट ऑन अर्थ-आर्फन ऑफ इंडिया पुस्तक लिखने वाली विधि स्नातक पौलोमी पावनी ने आठ राज्यों के 50 अनाथालयों का किया भ्रमण, महसूस की दिक्कतें

लखनऊ। लखनऊ की बेटी पौलोमी पावनी शुक्ला देश में अनाथों की आवाज बनी है। सुप्रीम कोर्ट में अनाथ बच्चों को लेकर पौलोमी ने याचिका दाखिल कर अनाथों को हक दिलाने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट ने भी केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिका इसलिए अहम है कि पहली बार देश के दो करोड़ अनाथों को आरक्षण के दायरे में लाकर उनके विकास का मार्ग प्रशस्त करने की मांग की है।

''वीकेस्ट ऑन अर्थ–आर्फन ऑफ इण्डिया' पुस्तक लिखने वाली विधि स्नातक पौलोमी पावनी शुक्ला ने आठ राज्यों के पचास अनाथालयों का भ्रमण कर अनाथों की दिक्कतों को करीब से महसूस किया। केन्द्र व राज्य सरकार के महमको के कई विशेषज्ञों से बात करने के बाद पौलोमी ने पाया कि अनाथों को जीवन, शिक्षा व सामानता के मूल अधिकारों से ही अब तक वंचित कर रखा गया है। देश में अनाथों की संख्या भी कोई छोटी न होकर श्रीलंका जैसे देश के बराबर है। करीब दो करोड़ की जनसंख्या को उनके अधिकार दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची पौलोमी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तीन बातें रखी हैं। अनाथों को आरक्षण देने की वकालत करती उनकी याचिका में देशभर में अनाथों का सव्रे कराने की भी मांग की गयी है। पौलोमी ने अनाथों को शिक्षा, अधिकार व वित्तीय मदद में भी उनका जायज हक देने की मांग की। उन्होंने कहा कि अनाथों को छात्रवृत्ति, परीक्षाओं के लिए कोचिंग की सुविधा, आसान ऋण, शैक्षणिक संस्थाओं व नौकरियों में आरक्षण जैसे अधिकार देकर उनका स्तर सुधारना होगा। अनाथालय बनाने की भी मांग रू पौलोमी ने कहा कि देश में अभी भी कई राज्य हैं जहां पर एक भी अनाथालय नहीं है। करीब 117 जिलों में एक भी अनाथालय न होने के कारण बच्चों को सुरक्षित रखना चुनौतीपूर्ण काम है। ऐसे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर जिले में पांच–पांच अनाथालय बनाए जाएं। इसमें उम्र के अनुसार बच्चों को रखा जाए। अनाथ बच्चों के लिए शुरू हुई चाइल्ड लाइन योजना भी अभी तक देश के 664 जनपदों के मुकाबले सिर्फ 36 जनपदों में ही पहुंची है। केन्द्र सरकार की मौजूदा योजनाएं नाकाफी रू अनाथों के लिए चलायी जा रही योजनाएं दो करोड़ अनाथों के लिए नाकाफी हैं। बच्चों की सुरक्षा के लिए वर्ष 2018–19 में करीब 725 करोड़ की धनराशि आवंटित की गयी। देश में अनाथों की संख्या देखते हुए यह एक रुपये प्रति बच्चाध्प्रति दिन ही होती है। आईसीपीएस जैसी योजना के दायरे में भी मुश्किल से एक लाख बच्चे ही आते हैं।

सेना के हाथों सौंपी गई गंगा की सुरक्षा, जवान रखेंगे घाटों पर साफ–सफाई का ख्याल

लखनऊ। देश में गंगा का जलस्तर कम और प्रदूषित होता जा रहा है. जिसको लेकर सरकार काफी चिंतित है. सरकार की मदद के लिए भारतीय सेना ने भी नई पहले शुरू की है. सेना ने 532 पूर्व सैनिकों को गंगा सफाई अभियान के लिए नियुक्त किया है.

इन पूर्व सैनिकों की बटालियन को गंगा टास्क फोर्स नाम दिया गया है, जिन्हें गंगा की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है. ये सभी पूर्व सैनिक गंगा के घाट पर पेट्रोलिंग करेंगे और लोगों को गंगा में गंदगी फेंकने से रोकेंगे. सेना के ये जवान इलाहाबाद, कानपुर और वाराणसी में तैनात किए जाएंगे.

भारतीय सेना की यह टुकड़ी अगले तीन साल तक इस मिशन पर काम करेगी. स्वच्छ गंगा राष्ट्रीय मिशन के महानिदेशक राजीव रंजन मिश्रा ने बताया कि पूर्व सैनिकों को इसमे शामिल करना काफी अहम फैसला है, यह फैसला सेना की भूमिका पर विचार करने के बाद लिया गया है. यह गंगा की सफाई और अधिक से अधिक लोगों को इस मुहिम से जोड़ने का हिस्सा है. उन्होंने कहा कि सेना के जवानों की तैनाती से लोगों में अनुशासन आएगा.

गंगा टास्क फोर्स में भारतीय सेना के 9 अधिकारी शामिल हैं, जबकि 29 जेसीओ भी इसमे हिस्सा ले रहे हैं. ये सभी लोग कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी में गंगा के अलग–अलग घाटों पर तैनात किए जाएंगे.

(पृ. 1 का शेष) . . . **राजभर की भाजपा**. . . स्वतंत्र है। मंत्री राजभर ने कहा 'वर्ष 2017 में हुये विधानसभा चुनाव में पार्टी को चार सीटें मिली है। विधानसभा चुनाव में भाजपा को 150 सीटों पर जीत उनकी पार्टी के समर्थन से मिली है। वे हमारे सहयोग को कैसे भूल सकते है।' उन्होंने बैठक में अपने समर्थकों से कहा है कि उनकी पार्टी के लिये गठबंधन को जारी रखना कोई बाध्यता नहीं है। उन्होंने कहा, ष्हम जूठा भी खाये और जुड़े भी रहे, ऐसा नही होगा।ष् उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि प्रदेश में कैसा कार्य हो रहा है। एसबीएसपी के चार विधायक हैं उनमें से एक राजभर योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। श्री राजभर ने कहा कि 15 महीने तक इंतजार करने के बाद भी भाजपा सरकार ने लखनऊ में पार्टी कार्यालय के लिए कोई आवास नही दे रही है। सरकार ने अम्बेडकर पार्क में सुहेलदेव की मूर्ति स्थापित करने की मांग पूरी करने से मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने पार्टी की बहराइच को सुहेलदेव के नाम से पर्यटन जिला के रूप में घोषित करने की मांग को भी पूरा नहीं किया है। हालांकि भाजपा अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडेय ने एसबीएसपी को कई बार चेतावनी दी है। उन्होने कहा कि गठबंधन को कमजोर करने के लिए विवाद पैदा न किये जाये। गत 19 जून को वाराणसी में अजघर में एक समारोह का उद्घाटन करते हुए, श्री पांडेय से जब मीडिया ने पूछा कि स्थानीय एसबीएसपी विधायक कैलाश सोनकर का नाम उद्घाटन पट्टिका पर क्यों नहीं है तो भाजपा अध्यक्ष ने कहा, ष्स्थानीय विधायक का नाम नहीं लिखा था क्योंकि वह चोर है।ष् एसबीएसपी विधायक सोनकर 4500 बुनकरों को रिण देने तथा सब्सिडी के मामले में 600 करोड़ रुपये के घोटाले के आरोपी है। बुनकरों ने एसबीएसपी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया था। भाजपा अध्यक्ष ने उन्हें आश्वासन दिया कि घोटाले में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जाएगा चाहे वह विधायक ही क्यो न हो। हालांकि, सोनकर ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है क्योंकि वह दलित हैं। उन्होंने कहा, ष्मुझे राज्यसभा चुनावों में क्रॉस वोटिंग के कारण फंसाया गया है। लेकिन जनता जानती है कि चोर कौन है और आने वाले 2019 चुनावों में जनादेश से स्पष्ट हो जायेगा।ष् उन्होंने संकेत दिया कि लोग भाजपा के खिलाफ मतदान करेंगे। भाजपा और एसबीएसपी के बीच इस तरह की टकराहट काफी दिनों से चल रही है। इस बीच, एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने गुरुवार को कहा कि पार्टी एसबीएसपी की गतिविधियों पर नजर रखे है। उन्होने कहा कि भाजपा अपनी ओर से गठबंधन तोड़ने के लिए कोई कठोर निर्णय नहीं लेना चाहती हैं।

(पृ. 1 का शेष) . . . **अब बीएड डिग्री धारक**. . . रखें है जिसे डिग्री धारकों को पूरा करना होगा. प्राइमरी टीचर बनने के लिए इन्हें स्नातक में पचास प्रतिशत अंकों के साथ छह महीने का ब्रिज कोर्स पास होना आवश्यक है। साथ ही प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक बनने के लिए साथ–साथ टीईटी पास होना भी जरूरी है। 2010 में अधिसूचना जारी की गई थी जिसमें बीएड डिग्री धारक सिर्फ उच्च प्राथमिक स्कूलों में ही आवेदन करने तक सीमित थे। ये खबर बीएड अभ्यार्थियों के लिए किसी तोहफे से कम नही है।

(पृ. 1 का शेष) . . . **यूपी की जनता** . . . और उनका समर्थन मांगेंगे।

अमित शाह ने मोदी सरकार पर आए दिन निशाना साधने वाले विपक्षियों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि अमेठी और रायबरेली को सालों से अंधेरे में रखने वाले राहुल बाबा से हिसाब मांग रहे हैं, पहले वह बताएं कि उनकी चार पीढियों ने राज किया फिर भी देश का विकास क्यों नहीं हुआ। यूपी में जाति की राजनीति करने वाला एक कुनबा और जिसका कुनबा नहीं है वह भी हिसाब मांग रहे है। शाह ने कहा कि कांग्रेस, सपा और बसपा ने यूपी की जनता का खून चूसने के अलावा कोई काम नहीं किया। मोदी की इच्छाशक्ति ही थी कि इजरायइल और अमेरिका के बाद भारत ऐसा देश बना जिसने उरी हमले के बाद आतंकियों को उसी की भाषा में जवाब दिया और पाकिस्तान में घुसकर सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक की। मोदी सरकार में ही देश का मान बढ़ा जब हमने एक साथ 104 सेटेलाइट अंतरिक्ष में छोड़े और अमेरिका का रिकार्ड तोड़ा।

अमित शाह ने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता के बीच जाने में कार्यकर्ताओं को शर्म आए। मोदी–योगी सरकार ने गरीब, किसानों, महिलाओं के उत्थान के साथ ही बुनियादी सुविधाओं पर पूरा ध्यान दिया और आज करोड़ों जनता योजनाओं का लाभ ले रही है। इस बार भी भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला। आपने देखा होगा कि मंच पर कैसे 14 नेता हाथ में हाथ पकड़कर खड़े थे। इन लोगों की अपने राज्य के बाहर कोई पकड़ नहीं है। अब आप बताएं कि काशी में देवगौड़ा, बरेली में ममता दीदी और चंद्रबाबू नायडू को लखनऊ में कौन सुनेगा? यह सब मिलकर भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के हौसले को नहीं तोड़ सकते हैं।

(पृ. 1 का शेष) . . . **मादक पदार्थो के** . . . अवैध कारोबार में जो लोग प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से लगे हुए हैं, उन्हें चिन्हित किया गया। 2– ऐसे संवेदनशील क्षेत्रो को चिन्हित किया जाय, जहां मादक पदार्थो की ब्रिकी व उनके प्रयोग करने की शिकायत मिलती है। 3– मादक पदार्थो की बिक्री किस–किस रूप में (नशीला इंजेक्शन, दवाइयां आदि) किया जा रहा है, इसे भी चिन्हित किया जाय। 4– मादक पदार्थो के आदी व्यक्तियों पर विशेष निगाह रखकर मादक पदार्थ उपलब्ध कराने वालों पर पहुँच बनायी जाय। 5– ऐसे चिन्हित व्यक्तियों के विरूद्व अभियान चलाकर प्रभावी एवं वैधानिक कार्यवाही की जाय। 6– मादक पदार्थो के बेचने या रखने के आरोप में जो अपराधी जेल में बन्द है, उनके मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर विधिक कार्यवाही करायी जाय। जमानत पर छूटने पर ऐसे अभियुक्तों पर विशेष ध्यान दिया जाय कि वह पुनः उसी कार्य में तो लिप्त नहीं हो गये हैं। 7– गिरफ्तार अभियुक्तों व उनके सहयोगियोंधरिश्तेदारों द्वारा मादक पदार्थ के अवैध कारोबार से अर्जित सम्पत्ति की खोजबीन हेतु आर्थिक विवेचना करके अवैध अर्जित सम्पत्ति को सीजध्क्रीज किया जाय। 8– ऐसी दवाओं (डाइजापाम आदि) जिनका प्रयोग नशे के लिए किया जाता है, इसकी उपलब्धता पर नियंत्रण स्थापित किया जाय। 9– मादक पदार्थो से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता अभियान स्कूल, कालेजों आदि में चलाकर बच्चों को जागरूक किया जाय।

(पृ. 1 का शेष) . . . **सूखा ग्रस्त इलाकों में**. . . का इस्तेमाल करते हैं। इसमें चीन, इजराइल, इंडोनेशिया, रूस, मैक्सिको जैसे देश शामिल हैं।

कृषि मंत्री के मुताबिक चीन ने इस बारिश के लिए आर्थिक मदद देने की बात कही थी लेकिन बाद में उसके इंकार करने पर आइआइटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने अपने प्रयास इस कम को सफल बनाया।

पासवान का मायावती पर बड़ा हमला, कहा– नोटबंदी के दौरान 104 करोड़ बैंक में जमा करवाए

लखनऊ। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने मायावती पर बड़ा हमला बोला है। लखनऊ में अपना दल के संस्थापक डॉ सोनेलाल पटेल की 69वीं जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की। यहां मायावती पर हमला बोलते हुए पासवान ने कहा कि नोटबन्दी होती है, तो 104 करोड़ बैंक में जमा करवाती हैं और अब पूछ रही हैं कि स्विस बैंक में पैसा कैसे आया। उन्होंने आगे कहा कि चुनाव से पहले नारा होता है कि तिलक तराजू ओर तलवार, इनको मारो जूता चार और चुनाव के बाद हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश है। पासवान का यह बयान मायावती के द्वारा स्विस बैंक में जमा भारतीयों के धन में बढ़ोत्तरी को लेकर मोदी सरकार पर किए गए हमले का जवाब माना जा रहा है। इस कार्यक्रम में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

पासवान ने बोला विपक्ष पर तगड़ा हमला

विपक्ष पर हमला करते हुए रामविलास पासवान ने कहा कि मुसलमान की लोग बात करते हैं। क्या मुस्लिम बंधुआ मजदूर है? क्या मुसलमान मुलायम और अखिलेश को वोट देने के किये पैदा हुआ है? आखिर क्यों यूपी और बिहार में इन लोगों ने मुसलमान को मुख्यमंत्री नहीं बनाया?

उन्होंने कहा कि मोदी जी फकीर हैं और जाति से भी फकीर हैं। राम विलास पासवान ने कहा कि आज जो दलित हैं, उन्हें गांधी जी ने हरिजन कहा था। उससे पहले अछूत कहलाते थे। अंग्रेजों के समय 3 नेता थे जिन्ना, गांधी और आम्बेडकर। उन्होंने कहा कि जब तक जाति व्यवस्था इस देश से खत्म नहीं होती, बराबरी का अधिकार नहीं आ सकता।

इस देश को सबसे ज्यादा देर तक जाति व्यवस्था ने गुलाम रखा। देश में सबसे पहले जातिवादी व्यवस्था पर भगवान बुद्ध ने हमला किया था। महात्मा बुद्ध क्षत्रिय थे लेकिन सबसे पहले उन्होंने जातिवाद व्यवस्था के खिलाफ जिहाद छेड़ा था।

गुणवत्ता विहीन शौचालयों का निर्माण करा रहे हैं ठेकेदार

रामसनेहीघाट, बाराबंकी। सरकार द्वारा चल रही योजना स्वच्छता भारत मिशन की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को लेकर गांवों को ओडीएफ करने के लिए खर्च की जा रही करोड़ों की धनराशि में बड़ा घपला किया जा रहा है।

तहसील क्षेत्र की तीनों ब्लाको में चलाये जा रहे स्वच्छता मिशन में सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार करके लोगो को जागरूक करके शौचालय निर्माण के लिए बारह हजार रुपये लाभार्थी को दे रही है इतने पैसे से सिर्फ काम चलाऊ शौचालयों का निर्माण ही सम्भव है किंतु ग्राम प्रधान व सचिव सहित अधिकारी भी इस पैसे में कमीसन खोरी से बाज नही आ रहे ।

प्रति शौचालय कमीशन तय करने के बाद मोदी के मिशन ओडीएफ को ठेकेदारों को सौंप दिया गया है। गांवों में हो रहे शौचालयों के निर्माण में ठेकेदार जमकर अनियमितता बरत रहे हैं। लेकिन अधिकारी घटिया शौचालयों के निर्माण को लेकर फिक्रमंद नहीं है। आलम यह है कि घटिया सामग्री से निर्मित हो रहे शौचालय अफसरों के संज्ञान में है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हो रही है।

गांवों को खुले में शौंच मुक्त करने के लिए गांव– गांव शौचालय बनाने के लिए सरकार करोड़ो धनराशि दे रही है। लेकिन इस धनराशि में भी खेल हो रहा है।

अधिकांश जगहों पर स्वच्छता मिशन के तहत बन रहे शौचालय को ठेकेदार व ग्राम प्रधान स्वयं बनवा रहे हैं। ऐसे में ठेकेदार व प्रधान अपना मुनाफा निकालने से लेकर अधिकारियों को तय कमीशन देकर घटिया निर्माण करवा रहे हैं। ठेकेदार 12 हजार रुपये की लागत का शौचालय 8 से 9 हजार रुपये में बनाता है। घटिया शौचालयों की लगातार शिकायतों के बावजूद भी कोई अफसर गंभीरता से नहीं ले रहा है।

दरियाबाद के खरगवापुर व रानेपुर, जेठौति राजपूतान, बिबियापुर, सराय रज्जन, लालगंज,व बनीकोडर में भेंदुआ बहरेला, व अन्य ओ ड़ी एफ ग्राम पंचायत तथा पूरे डलई की चयनित ग्राम पंचायतों तथा पृस्कृत पंचायते शामिल है इसके अतिरिक्त अन्य तमाम गांवों में ठेकेदार शौचालय का निर्माण करा रहे हैं। इन गांवों में ठेकेदारी प्रथा पर शौचालय बनाएं जाने की शिकायत ब्लाक से लेकर डीएम तक हुई ,तथा आये दिन समाचारों की शुर्खिया भी बनी लेकिन जांच को पहुंचने वाले अधिकारी घटिया पीली ईंट मिलने पर केवल उसे बदलवा दिया।

लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। लालगंज सहित कई गांवों में मानक विहीन शौचालय बनवाये जा रहे हैं। जेठौति राजपुत्तान में भी घटिया सामग्री शौचालय के लिए पहुंची है। परंतु कोई भी प्रधानमंत्री के ओडीएफ मिशन में चल रही कमीशनखोरी को लेकर गम्भीर नहीं है। ब्लॉक स्तर पर बैठे अधिकारी व कर्मचारी मात्र कमीशन बाजी में रहकर सरकार की अति महत्वपूर्ण योजनाओं को धराशाही करने में लगे है ।

सूत्रों की माने तो ब्लाक से लेकर गांव तक शौचालय में तीन स्तर पर कमीशन है। यहां पर प्रति शौचालय एक हजार कमीशन निकाला जाता है। इसके बाद ठेकेदार शौचालय बनाकर खुद का मुनाफा निकालते हैं। जिससे प्रति शौचालय की धनराशि में दो से तीन हजार रुपए का खेल किया जा रहा है।

यही नहीं जिन गांवों में शौचालयों की संख्या सैकड़ों में हैं, वहां उच्चाधिकारियों को कमीशन पहुंचाने की बात कहकर ठेकेदार से नकद कमीशन भी लिया जा रहा है। क्या ऐसे ही मोदी व योगी का सपना साकार हो सकेगा जब उन्हीं के अधिकारी व कर्मचारी महत्वपूर्ण योजनाओ के प्रति भी गंभीर नजर नही आ रहे हैं ये अपने आप में एक प्रश्न बना हुआ है।

एमएसपी बढ़ने से होगा किसानों की आमदनी में इजाफा : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने के निर्णय को ऐतिहासिक बताते हुए इस फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

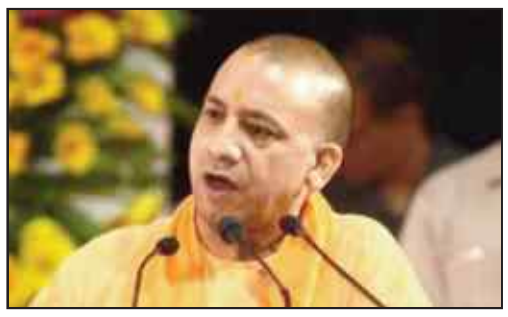

योगी ने कहा है कि इस निर्णय का लाभ प्रदेश के किसानों को भी प्राप्त होगा। योगी ने कहा, "कृषि को लाभकारी बनाने तथा किसानों की खुशहाली को बढ़ाने में केन्द्र सरकार का यह निर्णय महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।"

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आमदनी को बढ़ाकर दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार एक कार्य योजना बनाकर गम्भीरता से कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। पिछले महीने में केन्द्र सरकार द्वारा गन्ना किसानों के हित में घोषित किए गए चीनी उद्योग पैकेज के साथ–साथ खरीफ फसल के समर्थन मूल्य में वृद्धि सम्बन्धी इस निर्णय का प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

किसानों को राहत देने के लिए अहम फैसला किया

कैबिनेट ने 14 खरीफ फसलों की लागत से 50 प्रतिशत या उससे ज़्यादा न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. राजनीतिक तौर पर सबसे महत्वपूर्ण फसल धान की सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थन मूल्य 1550 रुपये से बढ़ाकर 1750 रुपये कर दिया गया है जो धान की लागत से 50.09: ज़्यादा है.

धान के बाद सबसे अहम फसल अरहर, मूंग और उड़द दाल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में भी काफी बढ़ोत्तरी की गई है. अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 5450 से बढ़ाकर 5675 रुपये प्रति क्विंटल हुआ है, जो अरहर की लागत से 65.36: ज़्यादा है सबसे ज़्यादा इजाफा बाजरा में किया गया है।

अफगानिस्तान में मारे गए सिखों को लखनऊ में श्रद्धांजलि

लखनऊ। अफगानिस्तान के जलालाबाद में हाल में हुए आत्मघाती हमलें में सिख समुदाय के विख्यात नेता अवतार सिंह खालसा और रावेल सिंह समेत 18 सिखों की मौत पर लखनऊ के सिख समाज मे खासा रोष है।

आपको बता दे अफगानिस्तान के जलालाबाद में आतंकवादियों द्वारा आत्मघाती हमले में कई सिखों की जान चली गयी है जिसको लेकर लखनऊ के नाका गुरुद्वारे में लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से बैठक बुलाई गई जिसमें सिख समाज के लोग बड़ी तादाद में उपस्थित हुए।

वहीं इस बैठक में विशेष तौर से कई धर्मो के धर्मगुरु भी उपस्थित हुए जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ आवाज बुलंद की और यह निर्णय लिया कि इस आतंकवादी हमले के विरोध में सिख समाज के साथ सभी समाज के आम लोग सड़क पर उतर कर मशाल जुलूस निकालेंगे और जिनकी मृत्यु हुई है इस हमले में उनकी श्रद्धांजलि के लिए कैंडल मार्च निकाला जाएगा। बैठक में मौजूद विभिन्न धर्मगुरुओ ने केंद्र सरकार से उनकी सुरक्षा की अपील करी। इस हमले को गंभीरता से ले और अफगानिस्तान सरकार पर

ड्रेसकोड लागू करने के निर्णय पर योगी सरकार का यूटर्न

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मदरसों में ड्रेसकोड लागू करने के अपने निर्णय पर योगी सरकार ने यूटर्न ले लिया है। अब उत्तर प्रदेश के मदरसों में कोई ड्रेसकोड लागू नहीं किया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस मामले में प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद योगी सरकार ने इस मामले को फिलहाल ठन्डे बस्ते में रख दिया है।

अल्पसंख्यक कल्याण और मुसलिम वक्फ हज मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने इस प्रकार के किसी भी प्रस्ताव से इनकार किया है। हालांकि अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा अपनी बात पर कायम हैं। अब वह इसे अपना खुद का प्रस्ताव बता रहे हैं।

मामले में मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार, राहुल गुप्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित मदरसों में किसी प्रकार का ड्रेस कोड निर्धारित किए जाने का प्रस्ताव परिषद की किसी भी बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही इस तरह का कोई निर्देश शासन स्तर से प्राप्त हुआ है।

अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का कहना है, मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं। यह मेरा एक सुझाव है। हमारे समाज को जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम उनको मुख्य धारा में जोड़ना चाहते हैं, तो हम उसी पर हैं।

उन्होंने कहा कि मुख्यधारा से जोड़ने के लिए उन्हें ड्रेस कोड देना होगा। बच्चे क्लास रूम में छात्र बनकर जाएंगे तो एक फील आएगा। इसके लिए हम सरकार को प्रस्ताव देंगे, क्योंकि यह हमारा ही प्रपोजल है। ऐसा नहीं है कि सरकार का निर्णय हो गया है। इसको इसलिए रखेंगे, क्योंकि उन्हें अलग–थलग नहीं छोड़ सकते।

उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यक राज्यमंत्री होने के नाते जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं, हमने जिस तरह से योगी जी के नेतृत्व में एनसीईआरटी की शिक्षा लागू की है। अगर मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ में सामाजिक शिक्षा और उन्हें ड्रेस कोड मिलेगा, उनके परिवार के लोग भी खुद को गौरवान्वित करेंगे।

कुर्ता–पजामा हमारा धार्मिक ट्रेडिशनल ड्रेस नहीं है।

यूपी में हुए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट का सख्त

निर्देश,15 दिन में रिपोर्ट तलब करें सीएम

नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में जगह जगह हो रही विभिन्न घटनाओं में अपराधियों की धरपकड़ तथा ऑपरेशन ऑल आउट के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीरता से सवाल उठाया है।

वहीं सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में हुए एनकाउंटर को लेकर योगी सरकार से जवाब भी मांगा है। यह जवाब प्रदेश सरकार को 2 हफ्तों में देना होगा। दरअसल पीयूसीएल एनजीओ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। बता दें कि पीयूसीएल एनजीओ ने अपनी याचिका में कहा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के तहत कई फर्जी एनकाउंटर किए गए हैं। इस मामले में की सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानविलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की एक खंडपीठ कर कर रही है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि पीयूसीएल (पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी) एनजीओ मानवाधिकारों के लिए काम करती है। एनजीओ ने यूपी में हुए 500 एनकाउंटर और 58 लोगों की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए उत्तरप्रदेश सरकार को जल्द से जल्द जवाब तलब करने को कहा है।

कात्यायनी देवी मंदिर से भव्य शोभायात्रा, सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद

अटरिया, लखनऊ। अटरिया क्षेत्र के कंटाइन गांव में स्थित सिद्धी पीठ माता कात्यानी देवी मन्दिर से बुधवार को भव्य शोभा यात्रा निकाली गई । यज्ञ में आए विद्वतजनों की टोली ने यज्ञ में आमंत्रित देवी–देवताओं का विधि–विधान से पूजन–हवन एवं आरती कर उन्हें विसर्जन का कार्य संपन्न कराया।

और वही मूर्ति स्थापना को लेकर बैड बाजे के साथ माँ की भव्य शोभा यात्रा मनवा की काली मंदिर व दुर्गा मन्दिर व प्रसिध्द राजामान धाता टंकेश्वर महादेव व बालेश्वर महादेव मंदिर तक भव्य शोभा निकाली गई जिसमे जगह – जगह मंदिरों पर भक्तो द्वारा बारात का स्वागत व सत्कार किया गया. बारात जगह जगह के प्रसिद्ध

मंदिर से होकर पुनःकंटाइन के लिए रवाना हुई.

इस भीषण गर्मी के दौरान भी भक्तो का जोश देखते बन रहा था इसी दौरान मनवा की माता दुर्गा मन्दिर पर भण्डारे का आयोजन बाके बिहारी व रामकुमार ने किया शोभा यात्रा के भक्तो ने प्रसाद ग्रहण कर अपनी प्यास बुझायी। पूरा वायुमंडल जयघोष से गुंजायमान हो रहा था. यज्ञ के अंतिम दिन ग्रामीण इलाकों के पुरुष–महिलाओं की अपार भीड़ यज्ञ स्थल पर जुटी रही। भक्त अपनी श्रद्धा भक्ति के अनुसार चढ़ावा चढ़ाकर अंतिम दिन की पूजा हवन में भाग लेकर पुण्य के भागी बनें।

वैदिक मंत्रोच्चारण की अनुगूंज से पूरा क्षेत्र भक्ति भाव से सराबोर रहा। यज्ञ समापन पर मंदिर के महंत आचार्य पण्डित संजीव त्रिपाठी जी महाराज ने यज्ञ में शामिल सभी श्रद्धालु भक्तों का आभार व्यक्त करते हुए आशीर्वाद दिया। यज्ञ को सफल बनाने में देशराज सिह, महेन्द्र सिह, रुपेश सिह, पुष्पेन्द्र सिह, ग्राम प्रधान रामदास रावत शेर बहादुर सिह , बाके बिहारी, प्रान्सू कश्यप ,राम कुमार हरिनाथ सिह, कोटेदार अमरसेन आदि सैकणो भक्तो का योगदान सराहनीय रहा।

सपा सरकार से 7 गुना अधिक गेहूं खरीद की गई : सूर्य प्रताप शाही

लखनऊ। लखनऊ में आज कृषक सम्मेलन का आयोजन किया गया. इस सम्मेलन में केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे हैं. वहीं उनके साथ प्रदेश कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, सहकारिता मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, गन्ना मंत्री सुरेश राणा और रणवेंद्र सिंह भी कृषक सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए.

प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित कृषक सम्मेलन में केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह शामिल हुए हैं. इसके साथ ही प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप साही भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. इस दौरान उन्होंने उपस्थिति लोगों को सम्बोधित करते हुए न केवल सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही विपक्षियों पर भी हमला बोला.

कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने यूपी के 2 करोड़ 33 लाख किसान परिवारों की ओर से पीएम का धन्यवाद. दिया। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य

बढ़ाने के लिए पीएम का धन्यवाद दिया और कहा लोहिया और चौधरी चरण सिंह के सपनो को पीएम मोदी ने साकार किया. यूपीए सरकार में जितनी कीमत थी उतनी कीमत तो किसानों के लिए बढ़ा दी गई है. कल का दिन किसानों के लिए दीवाली का दिन था. सरकार ने सपा सरकार से 7 गुना अधिक गेंहू खरीददारी की गई है.

वहीं इस सम्मेलन में गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने कहा कि प्रधानमन्त्री मोदी किसानों से किये गए वादे पर खरे उतरे हैं. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में पिछली सरकारों ने चीनी मिलें बेंची लेकिन योगी सरकार ने बंद मिलों को भी चलाया.

अखिलेश और उनकी पत्नी डिंपल यादव शुरू कर रहे है नया व्यापार

लखनऊ। बांग्ला विवाद को पीछे छोड़ अब सपा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनकी पत्नी सांसद डिंपल यादव अब होटल व्यवसाय में हाथ आजमाने का मन बना चुके है और इस हेतु उन्होंने कानूनी कार्यवाई शुरू भी कर दी है. कब्रों के अनुसार होटल हजरतगंज में बनेगा और इसका नाम हिबिस्कस रखा जाएगा. होटल के लिए लखनऊ विकास प्राधिकरण के मानचित्र सेल में नक्शा पास कराने के लिए आवेदन भी दिया जा चुका है. गौरतलब है कि अखिलेश की संपत्ति को लेकर विपक्ष उन्हें कई बार घेर चुका है हाल ही में बंगला विवाद में एक बार फिर उनके महंगे बंगले पर सवाल उठे थे.

हाल ही में मगहर में संत कबीर दास के 620वें प्रकटोत्सव पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहा कि कुछ लोगों का मन अपने आलीशान बंगले से लगा हुआ है. बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में श्बंगला सरकारश ने गरीब लोगों के लिए शुरू

किए गए आवास परियोजनाओं को रोके रखा, लेकिन सूबे में जब से योगी आदित्यनाथ ठोस कदम उठाए हैं. योगी सरकार ने गरीब लोगों को रिकॉर्ड स्तर पर आवास मुहैया कराया है.

मोदी ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा,श्उनका मन बंगला पर लगा था, करोड़ों रुपये लगाकर बंगला बनाने वालों ने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया.श बहरहाल अखिलेश के होटल को लेकर अभी कोई बयानबाजी शुरू नहीं हुई है मगर इसकी प्रबल संभावना है.

सजा पूरी करने जा रहा हूं : नवाज शरीफ

इस्लामाबाद। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने घोषणा की कि वह जवाबदेही अदालत द्वारा उन्हें 10 साल जेल की सजा सुनाए जाने के बाद वह पाकिस्तान आ रहे हैं।

उन्होंने कहा कि उन्हें इसलिए सजा दी गई है, क्योंकि उन्होंने देश के 70 साल के इतिहास को बदलने की कोशिश की है। फैसला सुनाए जाने के कुछ घंटों बाद शरीफ ने अपनी बेटी मरयम नवाज के साथ लंदन में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया।

तीन बार प्रधानमंत्री रह चुके नवाज ने कहा कि यदि श्वोट के लिए सम्मान की मांग करने की सजा जेल है, तो मैं उसका सामना करने के लिए आ रहा हूं। उन्होंने कहा कि वह उन लोगों के गुलाम नहीं रहेंगे, जो अपनी शपथ और पाकिस्तान के संविधान का उल्लंघन करते हैं।

501 रपए में नया जियो फोन

मुंबई। उद्योगपति मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो ने जियो फोन टू उतारने की घोषणा की है। ग्राहकों को 15 अगस्त से यह फोन 2999 रपए में उपलब्ध होगा। कंपनी ने पुराने फीचर फोन और 501 रपए देकर नया जियो फोन देने की योजना भी लांच की है।रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं आम बैठक के बाद प्रेसवार्ता में अध्यक्ष श्री अंबानी ने गुरुवार को यह घोषणा की। इस मौके पर श्री अंबानी ने कई और ऐलान किए जिसमें स्पेशल जियो मानसून हंगामा आफर, फिक्सड लाइन ब्राडबैंड सेवा, जियो गीगा फाइबर, जियो गीगा राउटर और गीगा टीवी सेटटॉप बाक्स और गीगा टीवी कालिंग भी शामिल हैं। कंपनी ने 15 अगस्त से जियो फोन पर फेसबुक यू ट्यूब और व्हाट्सऐप सुविधा मुहैया कराने की घोषणा भी की है। जियो मानसून हंगामा आफर के तहत 21 जुलाई से 501 रपए में पुराने जियो फोन के बदले नया फोन मिलेगा। कंपनी ने कहा है कि ग्राहक किसी भी कंपनी का कोई भी पुराना फीचर फोन 501 रपए का भुगतान कर जियो फोन एक खरीद सकेगा। जियो फोन 2 में कई सुविधाएं होंगी। हारिजेंटन स्क्रीन बोर्ड के साथ

कई फीचर्स वाले इस फोन पर ग्राहक फेसबुक, व्हाट्सऐप और यूट्यूब का आनंद भी उठा सकेंगे।श्री अंबानी ने कहा कि कंपनी 15 अगस्त से देश के 1100 शहरों के घरों, छोटे, मध्यम और बड़े उद्यमों के लिए सबसे एडवांस फाइबर आधारित ब्राडबैंड कनेक्टिविटी सोल्युशन प्रदान करने जा रहे हैं। जियो गीगा फाइबर ब्रांडबैंड नाम से इस सेवा के जरिये घरों में बड़े स्क्रीन टीवी पर अल्ट्रा हाई डेफिनिशन मनोरंजन, लिोवग रूम में मल्टी पार्टी वीडियो कांफ्रेंसिंग, वायस एक्टिव वर्चुअल सहायता और वर्चुअल रियलिटी गौमग और डिजिटल खरीदारी की सुविधा का लाभ उठाया जा

महेंद्र सिंह धोनी ने खेला 500वां इंटरनेशनल मैच, ऐसा करने वाले बने तीसरे भारतीय खिलाड़ी

कार्डिफ। भारत और इंग्लैंड के बीच कार्डिफ में आज दूसरा ज्20 मैच खेला जा रहा है और आज खेले जा रहे दूसरे टी–20 मैच में मैदान पर उतरते ही पूर्व भारतीय कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी ने एक नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आज महेंद्र सिंह धोनी इंग्लैंड के खिलाफ अपने करियर का 500वा अंतर्राष्ट्रीय मैच खेल रहे हैं।

इसके साथ ही महेंद्र सिंह धोनी का अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 या 500 से अधिक मैच खेलने वाले आठवें खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी ने अब तक 90 टेस्ट, 318 एकदिवसीय और आज के टी20 मैच को मिलाकर 92 ज्20 मैच खेले हैं। महेंद्र सिंह धोनी के इस रिकॉर्ड के बारे में खुद आईसीसी ने ट्वीट करके बताया।

आज इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी–20 मैच में भारतीय टीम में शामिल होने के साथ ही महेंद्र सिंह धोनी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। महेंद्र सिंह धोनी से पहले अभी तक सचिन तेंदुलकर कुमार संगकारा, रिकी पोंटिंग, महेला जयवर्धने, जैक कालिस, राहुल द्रविड़ और सनत जयसूर्या अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 500 से अधिक मैच खेल चुके हैं।

अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा मैच खेलने का रिकॉर्ड क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर के नाम है। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान 664 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। सचिन तेंदुलकर ने अपने करियर के दौरान 200 टेस्ट, मैच 463 एकदिवसीय मैच और एक टी20 मैच खेला था।

अंतर्राष्ट्रीय राजनीति व्यापार युद्ध के एक नये स्तर पर

नई दिल्ली। अंतराष्ट्रीय राजनीति एक नये स्तर पर आ गयी है । परम्परागत युद्ध और सम्राज्यवादी नीतियों से अलग ष्ट्रेड–वारष एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है। ट्रेड वार या व्यापार–युद्ध नयी पहचान बना चुका है जिसमें एक देश ,दूसरे देश के उत्पादों पर शुल्क बढ़ा देता है,बदले में दूसरा देश भी वैसा करता है जैसाकि इन दिनों अमेरिका का रुख देखने को मिल रहा है।

हाल ही कनाडा में सम्पन्न हुए ळ7 सम्मेलन में भी ये मुद्दा ज्वलंत बना रहा । इन दिनों भारत– अमेरिकी संबंधों में ष्2 प्लस 2 डायलॉगष का स्थगन कही ना कहीं ट्रेड वॉर का ही संकेत हैं। विस्तार से देखे तो अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प ने सम्पूर्ण अंतराष्ट्रीय संबंधों को झकझोर दिया है, आयात शुल्क बढ़ा कर। लगभग 25: स्टील पर एवम 10: इस्पात पर इम्पोर्ट टैक्स बढ़ाकर व्यापार–नियमो को

प्रभावित किया जिसके प्रतुत्तर में चीन ने भी अमेरिकी उत्पाद जैसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मिनरल्स इत्यदि पर टैरिफ बढ़ा दिया है।

विश्व के अन्य देश भी इस ट्रेड–वार में कूद चूके है जहाँ यूरोपीयन–यूनियन ने भी इम्पोर्ट टैक्स में 20:तक इजाफा किया है वही अमेरिका ने भी ॅज्ज के नियमो को दरकिनार कर सभी यूरोपियन कारो पर टैक्स बढ़ा दिया है। भारत भी अपने कुल निर्यात का लगभग 16: अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है ऐसे में टैरिफ शुल्क का बढ़ना आर्थिक संकट की ओर ले जायेगा । भारतीय व्यापार की शीर्षस्थ संस्था श्एसोचौमश ने भी स्पष्ट किया है डॉलर की अधिक मांग से करंट–एकाउंट डेफिसिट और जीडीपी पर भी अतिरिक्त दबाव आएगा ,भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

इस प्रकार वर्तमान में ष्अर्थव्यवस्थाष केंद्र बिंदु बन चुकी है। सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में लगे है लेकिन इस तरह की असन्तुलित व सरल व्यापार नियम के इतर वाणिज्यिवाद , विकासशील देशों की फिस्कल–हैल्थ के लिये नुकसानदेह है। अमरीका का राष्ट्रीय–सुरक्षा व रोजगार–सृजन की चिंता का नाम लेकर कर टैरिफ को यू बढ़ा देना ,समग्र वैश्विक तंत्र को विकृत कर देगा क्योंकि हेल्थी–इकॉनमी ही किसी देश की असली ताकत होती है

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी एवं संपादक
हेमन्त कुमार मिश्रा
द्वारा पिन वर्क पब्लिकेशन हाउस, दादाबाड़ी कम्पाउन्ड, ठाकुरगंज, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से प्रकाशित

संपादक
हेमन्त कुमार मिश्रा

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र जनपद लखनऊ न्यायालय होगा।

इस अंक में प्रकाशित समाचारों में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर सात दिन के अंदर खंडन भेजे अन्यथा समाचार ''सत्य'' माना जायेगा।
संपादक

crimereview2012@gmail.com
मो: 9454552222